हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 340 बेमेतरा, गुरुवार 06 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

पहला कॉलम

जेन-ज़ेड को टारगेट करने का प्लान! जैश आतंकी हमीम मंडल, अर्पिता से पूछताछ

कोलकाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के मुताबिक, गिरफ्तार किए दो लोग, हमीम मंडल और अर्पिता से पूछताछ में जैश-ए-मोहम्मद और आईएसआई से उनके कथित लिंक के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं. एनआईए अधिकारियों को शक है कि बंगाल के युवाओं को टारगेट करके एक कट्टरपंथी नेटवर्क बनाने की एक संगठित प्रयास चल रहा था. इसके बारे में विस्तार से पता लगाने के लिए उनसे कड़ी पूछताछ जारी है. पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने कथित जासूसी नेटवर्क की जांच के सिलसिले में सोमवार को हावड़ा से आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध गुर्गे हमीम मंडल के एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान आदित्य सिंह उर्फ राज उर्फ राजू के रूप में हुई है

शेख हसीना की पार्टी पर लगी पाबंदियां हटे

तसलीमा नसरीन

कोलकाता। बांग्ला की प्रसिद्ध लेखिका तसलीमा नसरीन ने आज कहा कि, बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी पर लगी पाबंदियां हटाना चाहिए और उन्हें दोबारा राजनीति में आने दिया जाना चाहिए। तसलीमा ने धर्म आधारित राजनीति का विरोध करते हुए कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों और समाज, दोनों के लिए नुकसानदेह है। तसलीमा नसरीन ने उक्त बात उत्तर 24 परगना जिले के सोदपुर स्थित पानीहाटी उच्च बालिका विद्यालय में महिला शिक्षा की अग्रदूत बेगम रुकैया सखावत हुसैन की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद कही। तसलीमा नसरीन ने अपने वतन बांग्लादेश लौटने को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी अभी भी अनिश्चित है। तसलीमा ने कहा कि यदि जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उनके अनुसार, यह संगठन शरीयत कानून और महिला विरोधी नीतियों का समर्थन करता है, जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खतरा बन सकती हैं।

आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एम्स ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाराम को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उनकी सेहत को देखते हुए 24 घंटे प्रशिक्षित देखभाल करने वालों (केयरगिवर्स) की मदद जरूरी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आसाराम कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एम्स की रिपोर्ट में आसाराम की बीमारियों का भी जिक्र किया गया है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वयंभू संत आसाराम कई बीमारियों से पीड़ित है।

मोदी सरकार ने संसद में नया विधेयक पेश किया

संसद में विधेयक पेश-2000 रुपये यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा

नई दिल्ली/ एजेंसी

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार अब उसे सरकारी तिजोरी भरने का जरिया के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। जी हां मोदी सरकार यूपीआई पेमेंट के नियम में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत 2000 रुपये से लेकर उससे अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा। मोदी सरकार ने संसद में नया विधेयक पेश किया है, जिसके तहत एमडीआर चार्ज की वापसी हो रही है। इसके तहत 2000 रुपये के ऊपर पेमेंट पर चार्ज देना होगा। वित्त मंत्रालय ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2027 पेश किया है। इस बिल के तहत मर्चेंट डिस्काउंट रेटलागू करने की बात कही गई है। यह चार्ज 2000 रुपये से ज्यादा की लिमिट पर लागू किया जा सकता है। इसका मतलब लोगों को एमडीआर चार्ज देना होगा। हालांकि राहत वाली बात यह है कि यह सभी लोगों पर लागू नहीं होगा। आम यूजर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह चार्ज सिर्फ बड़े व्यवसाय से जुड़े लोगों पर लगेगा। दूध, सब्जियां, किराने का सामान जैसी रोजमर्रा की खरीदारी और ऑटो रिक्शा व टैक्सी के किराए पर इसका असर पड़ने की

संभावना नहीं है। मीडियो रिपोर्टस के मुताबिक यह प्रस्ताव मुख्य रूप से 2,000 से अधिक के व्यापारी लेनदेन और बड़े कमर्शियल संस्थानों को टारगेट करता है। इससे कंज्यूमर टू कंज्यूमर्स के बीच हुए ट्रांजेक्शन को छूट होगी। अगर आप 2000 रुपये से ज्यादा का भी पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। सामान्य यूपीआई सीमा 1 लाख प्रतिदिन पेमेंट कर सकते हैं और कुछ स्पेशल कैटेगरी (जैसे अस्पताल, शिक्षा, टैक्स) में इससे कहीं अधिक सीमा तक पेमेंट कर सकते हैं। यह मुख्य तौर पर बैंक, यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर, मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम, भीम यूपीआई के माध्यम से छोटे भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर पड़ता है, क्योंकि इंसेंटिव इन्हीं ट्रांजेक्शनों के आधार पर दिया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक, 95 फीसदी 2000 रुपये से ज्यादा की लिमिट से कम वाले ही ट्रांजेक्शन होते हैं। सिर्फ 5 फीसदी ही ट्रांजेक्शन 2000 रुपये से ज्यादा का होता है। इसका मतलब है कि इन 5 फीसदी ही मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर ये चार्ज लागू होगा। रिपोर्ट के अनुसार, 2000 रुपये से ऊपर के व्यावसायिक लेन-देन पर प्रस्तावित शुल्क 0.25 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत तक हो सकता है, और 25-30 बेसिस पॉइंट्स तक के शुल्क पर भी चर्चा चल रही है। इसके लागू होने की समयसीमा पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

गलतियां बताए तो राम-विरोधी, करप्शन बताए तो देश-विरोधी! संसद के बाहर कांग्रेस का बड़ा मार्च

दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान आज भी संसद के बाहर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य विपक्षी सांसदों ने प्रेरणा स्थल पर गांधी जी की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मार्च के दौरान कहा कि हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं और बयान दें। अगर चर्चा होती है, तो हम उसमें शामिल होने को तैयार हैं। चर्चा से ही समाधान निकल सकता है। अगर चर्चा नहीं होगी, तो वे घर पर बैठकर बयान देंगे या चुप रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वे संसद का अपमान कर रहे हैं। वे सदन के अंदर नहीं आना चाहते। संसद शुरू हुए इतने दिन हो गए हैं। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? संसद के बाहर कांग्रेस का यह मार्च 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई', अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में निकाला गया।

अनुच्छेद 370 पर बड़ा संदेश

7 साल में बदली जम्मू-कश्मीर की तस्वीर-पीएम नरेन्द्र मोदी...

नई दिल्ली/ एजेंसी

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो चुके है। इन 7 सालों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आए बड़े बदलावों को लेकर प्रधानमंत्री ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर कहा कि इन वर्षों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। इसके साथ ही, पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, सात साल पहले इसी दिन (5 अगस्त को) अनुच्छेद 370 और 35(ं) इतिहास बन गए, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। तब से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता व खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें भारत के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन के कारण सशक्त बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल 5 अगस्त का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी वर्ष हमारा देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुआ। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को दिए निर्देश

बिना इंश्योरेंस के अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पेट्रोल पंपों पर ईंधन की सप्लाई को गाड़ियों के इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस प्रोजेक्ट का मकसद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जरूरी थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नियमों का पालन बेहतर बनाना है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर एक पायलट सिस्टम तैयार करे। इस सिस्टम के तहत, जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, उन्हें तब तक फ्यूल देने से मना किया जा सकता है, जब तक कि उनका इंश्योरेंस रिन्यू न हो जाए। ये निर्देश नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील पर सुनवाई के दौरान जारी किए गए, जिसमें कोर्ट ने मोटर इंश्योरेंस कवरेज और सड़क सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दों पर भी बात की। बेंच ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कोर्ट में हुई चर्चा के आधार पर, आईआरडीए के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट पर विचार करना चाहिए। और उसे तैयार करना चाहिए, जिसके तहत गाड़ियों के लिए फ्यूल (ईंधन) को उनके वैलिड इंश्योरेंस स्टेटस से जोड़ा जा सके। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित गाड़ी को पेट्रोल पंप पर तब तक ईंधन नहीं दिया जाएगा।

एएनपीआर कैमरों पोर्टल से जोड़ने के आदेश

कोर्ट का यह प्रस्ताव देश भर में अनिवार्य मोटर इंश्योरेंस को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जारी किए गए निर्देशों का एक हिस्सा है। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि हाईवे और सड़कों पर लगे एएनपीआर कैमरों को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डेटाबेस और वाहन पोर्टल से जोड़ा जाए, ताकि बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों के लिए अपने-आप ई-चालान बन सकें। राज्य पुलिस कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है।

कांग्रेस का आरोप, जवाब से बच रही सरकार इसलिए नहीं चल पा रही संसद

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में हेराफेरी, संसद में चर्चा की मांग, उत्तर प्रदेश के मदरसा विवाद मुद्दों पर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए सदन नहीं चल पा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और सरकार को आरोपों पर जवाब देना चाहिए।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा

अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना जमीन के उपयोग पर नहीं लगाई जा सकती रोक

ठछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना भूमि के उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश को मनमाना बताया। रायगढ़ जिले में कलेक्टर ने 4 फरवरी 2005 को रायगढ़-रेगपाली, रायगढ़-खरसिया, रायगढ़-सारंगढ़ और रायगढ़-धर्मजयगढ़ राष्ट्रीय राजमार्गों की सेंटर लाइन से 100 फीट के दायरे में आने वाली जमीनों के क्रय-विक्रय और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस आदेश को मनमाना बताते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पूर्व फैसले को अलग भूखंडों और अलग याचिकाकर्ताओं से संबंधित बताते हुए वर्तमान मामले में स्वत: लागू नहीं होने की दलील दी। कोर्ट ने पाया कि कानूनी स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। हालांकि, शासन की ओर से ऐसा कोई ठोस अंतर नहीं बताया जा सका, जिसके

आधार पर वर्तमान मामले में अलग निष्कर्ष निकाला जाता। हरिकृष्णा पटेल व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच के 3 फरवरी 2025 के फैसले का हवाला दिया। एकल पीठ ने कहा कि पूर्व में इसी आदेश के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा कानूनी स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। वर्तमान मामले में उससे अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई विशिष्ट आधार सामने नहीं आया है। इस निर्णय से उन भूमिस्वामियों को राहत मिली है, जिनकी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग की सेंटर लाइन से 100 फीट के दायरे में होने के कारण लंबे समय से खरीद-बिक्री और निर्माण संबंधी प्रतिबंधों से प्रभावित थी।

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक जयराम महतो झारखंड के धनबाद जिले में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए।

ई-20 डीपफेक केस में गडकरी को राहत

सोशल मीडिया प्लेफार्मस तुरंत हटाएं सभी पोस्ट.....

नई दिल्ली। ई-20 डीपफेक केस में नितिन गडकरी को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ ऑनलाइन डीपफेक पोस्ट को अश्लील, अपमानजनक और मान हानिकारक बताते हुए सोशल मीडिया प्लेफॉर्मस को उन्हें हटाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने गडकरी को मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक्स कॉर्प, गूगल और अनजान ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ बदनाम करने वाले और एडिट किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सिविल केस करने की इजाजत दी है। दरअसल केंद्रीय

मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित मानहानिकारक और डीपफेक कंटेंट के खिलाफ मानहानि याचिका दाखिल की थी।

साय कैबिनेट की बैठक संपन्न

छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी

रायपुर/ संवाददाता

मंत्रिपरिषद ने 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन' को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत – 100 एआई डेटा लैब बनाई जाएंगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज़ बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। यह मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार-आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बीईएमएल भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र हेतु

यह राज्य का पहला उद्योग होगा, जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी। मंत्रिपरिषद के इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। राज्य में संयंत्र की स्थापना से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद् ने लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एण्ड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी है। इस प्रणाली के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन तथा गुणवत्ता की निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।

लोक कलाकारों से प्रोत्साहन राशि हेतु 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित, चयनित कलाकारों को मिलेंगे प्रतिवर्ष 12 से 24 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि

लोक कलाओं के संरक्षण और कलाकारों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में संस्कृति विभाग की महत्वपूर्ण पहल

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना अंतर्गत राज्य के नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला (पारंपरिक व्यंजन) तथा छत्तीसगढ़ी सौंदर्यकला (श्रृंगार) से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.cgculture.in पर उपलब्ध हैं तथा संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, नया रायपुर स्थित कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन भेजते समय लिफाफे पर ÷मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026÷ स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा तथा समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। योजना के तहत पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह राशि एक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ केवल ऐसे कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ बैंक खाते का विवरण, आईएफएससी कोड तथा पैन कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। प्रविष्टियां भेजने का पता, संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर,द्वितीय तल, सेक्टर-27, नया रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़) ङ्क 492018 है। संचालक संस्कृति डॉ संजय कन्नौजे के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के अंतर्गत प्रदेश के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना, कलाकारों का सम्मान बढ़ाना तथा कला दलों के सतत विकास को नई गति प्रदान करना है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना प्रदेश की समृद्ध लोक कला परंपराओं के संरक्षण, कलाकारों के सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से लोक कलाकारों को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि अपनी कला को व्यापक पहचान दिलाने और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर भी प्राप्त होगा।

संवहनीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु कृषि सखियों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ

कोंडागांव/मूक पत्रिका

पवन कुमार नाग। ग्रामीण क्षेत्रों में संवहनीय कृषि को प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं की कृषि क्षेत्र में सहभागिता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अविनाश भोई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोण्डागांव के निर्देशानुसार 200 कृषि सखियों का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार से प्रारंभ हुआ।

यह प्रशिक्षण कुल 5 बैचों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक बैच में लगभग 40 कृषि सखियां भाग लेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि सखियों को संवहनीय कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जल संरक्षण, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन, पोषण वाटिका, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों तथा किसानों तक प्रभावी तकनीकी मार्गदर्शन पहुंचाने संबंधी व्यावहारिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सफल कृषि मॉडलों एवं नवाचारों से कृषि सखियों को अवगत कराया जाएगा, जिससे वे अपने-अपने ग्रामों में किसानों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।

कृषि सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विस्तार की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके माध्यम से आधुनिक एवं संवहनीय कृषि तकनीकों का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचेगा, जिससे उत्पादन लागत में कमी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा महिला किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

जर्जर सड़क से ग्रामीण बेहाल, पेड्रावन सरधाभाठा बालपुर मार्ग की मरम्मत की मांग

बड़े-बड़े गड्ढों और कीचड़ से आवागमन मुश्किल, दुर्घटना का बढ़ा खतरा

बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

बिलाईगढ़ क्षेत्र के पेड्रावन-सरधाभाठा-बालपुर सड़क मार्ग की जर्जर हालत से क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण सड़क जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। बरसात में मार्ग पर कीचड़ और जलभराव होने से दोपहिया वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क से डामर पूरी तरह उखड़ चुका है और कई स्थानों पर गहरे गड्ढों में पानी भरा रहता है। इससे आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद लोक निर्माण विभाग ने अब तक मरम्मत कार्य नहीं कराया।ग्रामीणों ने बताया कि इस पेड्रावन, सरधाभाठा और बालपुर के हजारों ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से आवागमन करना पड़ रहा है।क्षेत्रवासियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत कराकर डामरीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

औसत बारिश में सारंगढ़-बिलाईगढ़ और कुल बारिश में नारायणपुर जिला अव्वल

छत्तीसगढ़ में मानसून का अब तक 99.2त्न सामान्य वर्षा दर्ज

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

संभाग एवं जिलावार प्रमाण संख्या

आज दिनांक 05.08.2026 की स्थिति में वर्षा की जानकारी का विवरण अग्रांकित सारणी प्रस्तुत है – (वर्षा मि.मी.में)

क्र.	जिले का नाम	जिले की औसत वर्षा	5 अगस्त को जिले की प्रतिदिन दिनांक तक की वर्षा	जिले की आज तक औसत वर्षा की औसत वर्षा (पिछले 10 वर्षों के आधार पर)	जिले की वास्तविक औसत वर्षा की प्रतिशत	जिले की वास्तविक औसत वार्षिक वर्षा
1	सरगुजा	8.2	288.2	442.4	65.1	883.0
2	सूरजपुर	13.9	522.3	595.4	87.7	1148.5
3	बलरामपुर	17.5	542.1	471.2	115.0	1370.4
4	जशपुर	5.3	409.9	593.1	69.1	1157.5
5	कोरिया	18.5	495.1	531.7	93.1	1052.1
6	कोण्डागांव–बिजापुर–मध्यपुर	27.9	483.6	523.8	92.3	1052.4
7	धमतरी	16.1	637.4	490.3	130.0	1085.0
8	बलौदाबाजार	26.9	653.6	559.3	116.8	1070.9
9	गरियाबंद	2.6	717.6	566.9	128.9	1296.1
10	महासमुंद	9.0	743.0	533.5	139.3	1081.7
11	कांकेर	2.2	642.5	569.2	112.9	1352.4
12	बिलासपुर	9.9	603.4	560.6	107.6	1215.5
13	दुर्ग-सी	12.2	545.7	539.6	101.1	1010.3
14	रायगढ़	9.6	565.5	514.2	92.1	1338.0
15	सारंगढ़–बिलाईगढ़	19.1	838.6	450.5	186.2	979.8
16	जांजगीर चांपा	11.8	763.8	611.4	124.9	1461.8
17	सक्ती	14.1	619.7	543.5	114.0	1157.0
18	कोरबा	12.1	588.9	635.4	92.7	1368.2
19	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	21.8	545.5	573.9	95.1	1288.7
20	दुर्ग	11.9	501.0	439.0	114.1	951.4
21	कबीरधाम	3.5	362.9	444.8	81.6	919.6
22	राजनांदगांव	4.8	516.6	513.4	100.6	1051.0
23	मोहला–मानपुर–अ.चौकी	17.6	528.6	704.4	75.0	1467.8
24	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	22.6	403.2	423.1	95.3	1055.6
25	बालोद	8.1	652.3	562.9	121.2	1255.0
26	बेमेतरा	18.2	343.4	446.5	76.9	891.5
27	बलौदा	4.0	558.6	721.3	77.4	1563.0
28	गरियाबंद	6.1	588.2	661.0	89.0	1327.4
29	बालोद	11.9	567.4	798.3	71.1	1407.6
30	जांजगीर–चांपा	2.6	1004.1	711.4	141.1	1440.8
31	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	11.7	745.9	759.3	98.2	1575.1
32	सूरजपुर	9.0	545.0	811.6	67.2	1409.5
33	बीजापुर	8.9	746.9	1059.1	70.4	2141.3

छत्तीसगढ़ में इस वर्ष मानसून की स्थिति कुल मिलाकर सामान्य और संतोषजनक बनी हुई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 5 अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 1 जून से अब तक औसतन 584.8 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो कि इस अवधि की सामान्य औसत वर्षा (589.5 मिमी) का 99.2 प्रतिशत है। प्रदेश में 5 अगस्त को राज्य का दैनिक औसत 12.1 मिमी दर्ज किया गया। आंकड़ों के अनुसार, औसत के मुकाबले प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक वर्षा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में हुई है, जहाँ सामान्य औसत (450.5 मिमी) के मुकाबले 186.2प्रतिशत (838.6 मिमी) बारिश दर्ज की गई है। वहीं कुल वर्षा की मात्रा के मामले में नारायणपुर जिला सबसे आगे है, जहाँ अब तक 1004.1 मिमी (141.1प्रतिशत) वर्षा हो चुकी है। इसके अलावा महासमुंद (139.3प्रतिशत), रायपुर (130.0प्रतिशत), गरियाबंद (128.9प्रतिशत), जांजगीर-चांपा (124.9प्रतिशत), बालोद (121.2प्रतिशत), बलौदाबाजार (116.8प्रतिशत), बलरामपुर (115.0प्रतिशत), दुर्ग (114.1प्रतिशत), सक्ती (114.0प्रतिशत) और धमतरी (112.9प्रतिशत) जिलों में भी सामान्य से काफी बेहतर बारिश दर्ज की गई है।

सरगुजा और सुकमा में सामान्य से कम बारिश-प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। सरगुजा जिले में औसत का महज 65.1प्रतिशत (288.2 मिमी) और सुकमा में 67.2प्रतिशत (545.0 मिमी) बारिश ही दर्ज हुई है। ?इसके अलावा जशपुर (69.1प्रतिशत), बीजापुर (70.4प्रतिशत), कांकेर (71.1प्रतिशत), मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (75.0प्रतिशत), बेमेतरा (76.9प्रतिशत), बस्तर (77.4प्रतिशत) और कबीरधाम (81.6प्रतिशत) जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम बना हुआ है। राज्य के सभी 33 जिलों में 1 जून से 5 अगस्त 2026 तक ?सरगुजा संभाग के सरगुजा में 288.2 मिमी (65.1प्रतिशत), सूरजपुर में 522.3 मिमी (87.7प्रतिशत), बलरामपुर में 542.1 मिमी (115.0प्रतिशत), जशपुर में 409.9 मिमी (69.1प्रतिशत), कोरिया में 495.1 मिमी (93.1प्रतिशत) तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 483.6 मिमी (92.3प्रतिशत) वर्षा दर्ज की गई है। रायपुर संभाग के रायपुर जिले में 637.4 मिमी (130.0प्रतिशत),बलौदाबाजार में 653.6 मिमी (116.8प्रतिशत), गरियाबंद में 717.6 मिमी (128.9प्रतिशत), महासमुंद में 743.0 मिमी (139.3प्रतिशत) और धमतरी में 642.5 मिमी (112.9प्रतिशत) बारिश हुई है। बिलासपुर संभाग के बिलासपुर में 603.4 मिमी (107.6प्रतिशत), मुंगेली में 545.7 मिमी (101.1प्रतिशत), रायगढ़ में 565.5 मिमी (92.1प्रतिशत), सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 838.6 मिमी (186.2प्रतिशत), जांजगीर-चांपा में 763.8 मिमी (124.9प्रतिशत), सक्ती में 619.7 मिमी (114.0प्रतिशत), कोरबा में 588.9 मिमी (92.7प्रतिशत) तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 545.5 मिमी (95.1प्रतिशत) वर्षा दर्ज की गई है। दुर्ग संभाग के दुर्ग जिले में 501.0 मिमी (114.1प्रतिशत), कबीरधाम में 362.9 मिमी (81.6प्रतिशत), राजनांदगांव में 516.6 मिमी (100.6प्रतिशत), मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 528.6 मिमी (75.0प्रतिशत), खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 403.2 मिमी (95.3प्रतिशत), बालोद में 682.3 मिमी (121.2प्रतिशत) और बेमेतरा में 343.4 मिमी (76.9प्रतिशत) वर्षा हुई है।

जिला अस्पताल परिसर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, बाइक बरामद

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ उत्तर बस्तर कांकेर की थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने शासकीय कोमलदेव जिला अस्पताल परिसर से हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले का सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गई होंडा लियो मोटरसाइकिल (क्रमांक छ्त्त 19 क्ष्त्त 2967), जिसकी अनुमानित कीमत ?30,000 है, बरामद कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी घनश्याम शोरी (निवासी पंडीपारा हरनपुरी, थाना कोरर) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 अगस्त 2026 को वह अपनी मोटरसाइकिल से शासकीय कोमलदेव जिला अस्पताल कांकेर पहुंचे थे। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर वे अस्पताल के अंदर भोजन देने गए थे, लेकिन वापस लौटने पर वाहन गायब मिला। काफी खोजबीन के बाद भी जब बाइक का पता नहीं चला, तो उन्होंने सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराया। शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 261/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने तकनीकी साधनों और मुखबिर सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। पतासाजी के दौरान शासकीय शराब दुकान पण्डरीपानी के पास संदेह के आधार पर नीरज नाग (42 वर्ष, निवासी ग्राम हाटकोंगेरा) को रोककर पूछताछ की गई, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद हुई। आरोपी ने स्वयं के उपयोग के लिए अस्पताल परिसर से गाड़ी चोरी करने की बात कबूल कर ली। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी अपराध क्रमांक 251/2024 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को 4 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक जितेन्द्र साहू, सहायक उपनिरीक्षक सोमेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक गीतेशवर कुलदीप, आरक्षक रोशन राठौर, ईश्वर साहू, पुरन साहू तथा निरीक्षक यशवंत साहू के नेतृत्व वाली साइबर टीम की सराहनीय भूमिका रही।

बचेली के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग में लहराया परचम, दो स्वर्ण समेत पांच पदक जीतकर दंतेवाड़ा का बढ़ाया मान, कोच नंदकिशोर साहू भी सम्मानित

गीदम/दंतेवाडा/मूक पत्रिका

सीमांत अंचल दंतेवाड़ा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। धमतरी में आयोजित 12वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बचेली के पांच खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण और तीन कांस्य पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिली है। प्रतियोगिता के दौरान टीम के कोच नंदकिशोर साहू को भी पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक अग्रसेन भवन, सिहावा चौक, धमतरी में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कोच नंदकिशोर साहू के नेतृत्व में बचेली नगर के पांच खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में हिस्सा लिया। जूनियर 84 किलोग्राम वर्ग में श्रुति साहू ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। वहीं सीनियर 84 प्लस किलोग्राम वर्ग में शिप्रा बिस्वास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके अलावा सीनियर 84 किलोग्राम वर्ग में दीपाली सरकार, सीनियर 64 किलोग्राम वर्ग में शोभा बघेल तथा जूनियर 74 किलोग्राम वर्ग में चित्रंजन दास ने कांस्य पदक जीतकर जिले के पदकों की संख्या पांच तक पहुंचाई। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रतियोगिता में सराहा गया। समापन समारोह में कोच नंदकिशोर साहू को पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए स्मृति-चिन्ह (मोमेंटो) प्रदान कर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर एनएमडीसी, नगर के जनप्रतिनिधियों तथा वेटलिफ्टिंग संघ बचेली के पदाधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों और कोच को बधाई देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।

रोजगार मेला में 55 आवेदकों का प्राथमिक चयन एवं 18 को स्थल पर ही मिला आफॅर लेटर

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे - कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में बुधवार को रोजगार कार्यालय बलौदाबाजार में 184 पदों हेतु रोजगार मेला का आयोजन किया गया।मेले में 107 आवेदकों द्वारा साक्षात्कार में भाग लिया गया जिसमें से 55 आवेदकों का प्राथमिक चयन कर 18 आवेदकों को मेला स्थल पर आफॅर लेटर प्रदान किया गया। जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार मेला में नियोजक कुंजीलाल फ्यूल बलौदाबाजार द्वारा सेल्स, मार्केटिंग एवं टेली के रिक्त पदों हेतु 25 आवेदकों द्वारा साक्षात्कार में भाग लिया गया, जिसमें 7 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया।

जिन्दल स्टील लिमिटेड मदिर हसौद द्वारा मशीनिष्ट के रिक्त पदों हेतु 18 आवेदक साक्षात्कार लिया गया जिसमें 12 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया है। दुर्गेश सिक्योरिटी सर्विसेस रायपुर द्वारा सेक्योरिटी गार्ड के रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार लिया गया जिसमें 30 आवेदक उपस्थित हुए इसमें से 20 आवेदकों का प्राथमिक चयन कर 12 आवेदकों को मेला स्थल पर ऑफर लेटर प्रदान किया गया। इंडिया हेल्प पोइंट रायपुर द्वारा मार्केटिंग के पदों हेतु साक्षात्कार लिया गया जिसमें 18 आवेदक उपस्थित हुए उसमें से 12 आवेदकों का प्राथमिक चयन कर 4 आवेदकों को मेला स्थल पर ऑफर लेटर प्रदान किया गया। जायका आटो मोबाईल रायपुर द्वारा सेल्स, तकनीशियन,सर्विस एडवाजर एवं कस्टमर केयर के रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार लिया गया जिसमें 16 उपस्थित हुए इसमें से 6 आवेदकों का प्राथमिक चयन कर 02 आवेदकों को मेला स्थल पर ऑफर लेटर प्रदान किया गया है। समस्त नियोजकों द्वारा प्राथमिक एवं अंतिम चयनित आवेदकों को एक सप्ताह के अंदर अपने अपने संस्था में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि चयन संबंधित अंतिम कार्यवाही पूर्ण किया जा सकें।

यातायात जागरूकता अभियान के साथ किये जा रहे सुरक्षा के उपाय

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

ताराचंद कठोत्रे बलौदाबाजार-भाटापारा में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा ब्लैक स्पॉट में दुर्घटना में कमी लाने जिले के दुर्घटनाजन्य स्पॉट सकरी बाई पास बलौदाबाजार में नियमों के प्रति जिम्मेदारी व सतर्कता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 05.08.2026 पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय (ढ्ढक्क्र) के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री खोमन सिन्हा के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री संजय कुमार साहू के नेतृत्व में यातायात पुलिस बलौदाबाजार के द्वारा दुर्घटनाजन्य स्पॉट में ड्रायवर संघ के सहयोग से भारी वाहन चालको , बस, एवं छोटे वाहन चालको को रोककर ब्रीथ एनालाईजर से चेक कर वाहन चलाते समय शराब एवं अन्य नशे से दुर रहने , गति सीमा में वाहन चलाने , ओव्हर टेक एवं रोड में वाहन न रखने के संबंध में हिदायत दिया गया साथ ही मुख्य मार्ग में घूमने वाले मवेशियों को ? रेडियम बेल्ट लगाया गया ताकि रोड में पशुधन की वजह से कोई असामयिक घटना न हो एवं आवागमन सुगम हो जिले के लवन, कसडोल, सिमगा, भाटापारा के दुर्घटनाजन्य स्थलो पर टिकली , ?रेडियम , स्टापर, संकेतक पटिका लगाया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस का व्यापक अभियान लगातार जारी।

ड्रायवरो को दुर्घटनाजन्य स्पॉट पर रोककर पढाया गया यातायात नियमों का 'सुरक्षा पाठ'! यातायात शाखा बलौदाबाजार की अनोखी पहल छत्तीसगढ ड्रायवर संघ कर रहे सहयोग। ड्रायवरो को नशे से दुर रहने किया गया जागरूक ।सडक मार्ग के आसपास घूमने वाले मवेशियों को लगाया जा रहा रेडियम बेल्ट। कर्व , दुर्घटना जन्य स्थलो में लगाया जा रहा टिकली , रेडियम

नागरमुडा में कट गए 40 हजार से भी ज्यादा पेड़, प्रतिबंधित सराई के पेड़ो को भी काटा गया, क्षेत्र का पर्यावरण होगा प्रभावित

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिले के लैलूंगा विधानसभा में स्थित तमनार ब्लॉक में कोयला खदान के आबंटन के बाद जिन्दल ने इलाके के नागरमुडा में बीते एक माह के भीतर 40 हजार से भी अधिक पेड़ो को काट दिया है, जबकि अनुमती लगभग 16 हजार पेडो की थी। इतना ही नही प्रबंधन ने अनुमती की आड में बेशकीमती सौगान व प्रतिबंधित सराई के पेड़ो को भी काटकर यह बता दिया है कि इलाके में उसे रोकने वाला कोई नही है।

इस संबंध में पर्यावरण प्रेमी व जन चेतना मंच के संयोजक राजेश त्रिपाठी बताते हैं कि जिंदल प्रबंधन ने वन विभाग से मिली अनुमती का न केवल मजाक उड़ाया है बल्कि हरे भरे इलाके को पूरी तरह नष्ट करते हुए वहां के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना था कि जिंदल उद्योग को प्रस्तावित कोयला खदान शुरू करने के लिये नागरमुडा भी आता है और इस इलाके में लगभग 50 से 60 हजार हरे भरे बेशकीमती

सराई तथा सौगान के पेड भी लगे हुए थे और अनुमती मिलते ही प्रबंधन ने वन विभाग की टीम के सामने मशीनों से पूरे इलाके को ठूंठ में बदल दिया है। राजेश त्रिपाठी बताते हैं कि नियमों की अनदेखी के साथ-साथ इस कटाई में जिंदल की मनमानी साफ तौर पर उजागर होती है, चूंकि नागरमुडा इलाके में सराई पेडो की बहुतायत है और इसको काटने की अनुमती कैसे मिल गई यह बडा प्रश्न है।

क्या कहते हैं अधिकारी-इस संबंध में वन विभाग के घरघोड़ा एसडीओ आशुतोष मांडवा ने बताया कि नागरमुडा गांव में जिन्दल की प्रस्तावित कोयला खदान के लिए विभाग से पेड़ कटाई की अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद विभाग ने 13537 पेड़ों को काटने की अनुमति दी है. मांडवा ने कहा कि कटाई की जद में जंगल में साल सहित कई प्रजाति के छोटे-बड़े पेड़ आएंगे।

काटे गए पेड़ो को जिंदल खुद कर रहा परिवहन-नागरमुड़ा इलाके में जिंदल उद्योग द्वारा वन विभाग की टीम के सामने मशीनों से विशालकाल पेड़ो की कटाई के बाद उन पेड़ो के ठूंठ एवं लकडियां खुद जिंदल अपने कब्जे में ले रहा है जबकि काटे गए पेड़ो को विधिवत वन विभाग अपने साथ ले जाता है, इतना ही नही क्षेत्र में बेतहाशा कटाई के कारण अब यह नागरमुडा जो कभी हरा भरा हुआ करता था अब ठूंठ में तब्दील हो गया है। अन्य सूत्र बताते हैं कि जिंदल प्रबंधन की इस मनमानी का विरोध तमनार ब्लाक के कई गांव के लोग कर रहे है और उनके विरोध के बाद भी यह कटाई जारी है।

कांग्रेस की चुप्पी भी संदेह के दायरे में-मजे की बात यह है कि जहां अडानी समूह द्वारा तमनार ब्लाक में पेड कटाई की जा रही थी तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई पूर्व मंत्री व विधायक विरोध करने के लिये पहुंच गए थे। लेकिन जिंदल उद्योग की इस कटाई पर पूरी कांग्रेस कमेटी ने जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक चुप्पी साध ली है।

लाखों का सामुदायिक शौचालय बना शोपीस: पानी के बिना बेकार, सरपंच-सचिव और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से जनता परेशान

खरसिया/मूक पत्रिका

तहसील के ग्राम पंचायत पतरापाली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में लाखों रुपये की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। जिस पर ज्यादा तर ताला लटका रहता है। निर्माण कार्य पूरा हुए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज तक शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। परिणामस्वरूप ग्रामवासी और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) से आने-जाने वाले लोग इस शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय बनने के बाद से ही यह उपयोग के अभाव में बंद पड़ा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पंचायत सचिव और सरपंच को इस समस्या की पूरी जानकारी होने के बावजूद इसे चालू कराने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। इससे स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।लाखों रुपये की सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद यदि आम जनता को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, तो यह संबंधित विभाग, पंचायत सचिव और सरपंच की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही पानी की व्यवस्था कर शौचालय को उपयोगी नहीं बनाया गया, तो वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत करने को मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं या फिर सरकारी धन से बना यह सामुदायिक शौचालय यूँ ही बंद पड़ा रहकर भ्रष्ट व्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता की मिसाल बना रहेगा।

धरती आबा अभियान से प्रत्येक ग्रामसभा को मिलेंगे 15 लाख रुपए, कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सारंगढ़ में 10 अगस्त तक प्रस्ताव आमंत्रित

सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनेगी विशेष योजना

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 160 ग्रामों का चयन करेगी। निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेज के साथ 10 अगस्त 2026 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कोसीर रोड सारंगढ़ में जमा किया जाना है। इन ग्रामों में सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना (सीएफआरएमपी) तैयार कर लागू की जाएगी। इस सम्बन्ध में आदिम जाति विभाग द्वारा कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्रामसभा में सामुदायिक संसाधन प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जो ग्रामसभा के वन माध्यम से योजना के क्रियान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी निभाएगी। इसके लिए ग्रामसभा के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में सिंगल करंट अकाउंट भी खोला गया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि राज्य सरकार ने जिलों से ऐसे आदिवासी गांवों का चयन क्लस्टर आधारित और परस्पर जुड़े क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। आयुक्त डी राहुल वेंकट द्वारा राज्य के सभी कलेक्टर को जारी पत्र में कहा गया है कि योजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार तकनीकी सहयोगी, सिविल सोसायटी संगठनों तथा स्थानीय संस्थाओं की सेवाएं भी ले सकेंगी। इन संस्थाओं की सेवाएं ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं विधिवत अनुमोदन के बाद ली जा सकेंगी। ये संस्थाएं ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन तथा निगरानी में सहयोग देंगी।

कांकेर में भालू का कहर: अलग-अलग घटनाओं में 3की मौत, मादा भालू के हमले से दहशत

मरकाटोला में भाई-बहन की दर्दनाक मौत, नरहरपुर क्षेत्र में बुजुर्ग ने भी गंवाई जान; वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद मादा भालू को किया काबू।

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल परिक्षेत्र में मंगलवार को भालू के हमले की दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पहली घटना मरकाटोला गांव की है, जहां एक मादा भालू अपने मृत शावक के पास काफी देर से बैठी थी और किसी को भी उसके करीब नहीं आने दे रही थी। वन विभाग की टीम शावक का रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय ले गई। इसके बाद उत्तेजित मादा भालू ने खेत में काम कर रहे हलालखोर जुरी (45) और उनकी बहन चमरिन जुरी (40) पर हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान शासकीय आश्रम से भोजन लेकर खेत पहुंची सौरिन जुरी (30) ने दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन भालू ने उस पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। दूसरी घटना नरहरपुर थाना क्षेत्र के सिहरिनाला गांव में हुई, जहां खेत गए 67 वर्षीय देवबली ध्रुवा पर भालू ने हमला कर दिया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन तलाश में निकले, जहां उनका शव खेत के पास मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।मरकाटोला में मादा भालू करीब पांच घंटे तक मृतकों के शवों के पास मंडराती रही, जिससे वन विभाग और पुलिस शवों को अपने कब्जे में नहीं ले सके। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तत्काल रेस्क्यू की मांग करने लगे। कांकेर विधायक भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। वन विभाग की स्थानीय टीम द्वारा रेस्क्यू के प्रयास सफल नहीं होने पर रायपुर से विशेष रेस्क्यू दल बुलाया गया। टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से मादा भालू को बेहोश कर काबू में लिया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीण भालू पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वन विभाग और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए भालू को सुरक्षित बचाया और कांकेर मुख्यालय ले गए। लगातार हो रहे वन्यजीवों के हमलों से जिले के ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

पेंशनरों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, 2 प्रतिशत डीआर का एरियर जारी करने की मांग

जनवरी 2026 से लंबित महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान को लेकर पेंशनर्स समाज जिला शाखा उत्तर बस्तर कांकेर ने उठाई आवाज

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ कांकेर पेंशनर्स समाज जिला शाखा उत्तर बस्तर कांकेर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) का आदेश एरियर सहित तत्काल जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार अपने पेंशनरों को जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभपहले ही प्रदान कर चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अब तक राज्य के पेंशनरों के लिए डीआर का आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे प्रदेश के लाखों पेंशनरों में निराशा व्याप्त है। पेंशनर्स समाज ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच आवश्यक सहमति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए अब डीआर का आदेश जारी करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। संगठन ने शासन से लंबित महंगाई राहत का आदेश एरियर सहित तत्काल जारी कर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश भट्ट ने कहा कि राज्य के सभी पेंशनरों के हित में शासन शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले, ताकि उन्हें उनका वैधानिक अधिकार और आर्थिक राहत मिल सके। संगठन ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द निर्णय लेकर प्रदेश के लाखों पेंशनरों को राहत प्रदान करेगी।

ब्लेड दिखाकर मोबाइल लूटने वाला शातिर बदमाश 6 घंटे में गिरफ्तार, कांकेर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ उत्तर बस्तर कांकेर के थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड पर हुई मोबाइल लूट की घटना का महज़ 6 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया ऋद्धड्डद्यद्वद्ग ष्ट35 मोबाइल भी बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करीब ?12,000 बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सयजू सलाम (निवासी मंगहूर, थाना बड़गांव) निजी काम से रायपुर गए थे। 2 अगस्त की रात वापस कांकेर पहुंचकर वे बस स्टैंड पर रुके हुए थे। 3 अगस्त की सुबह लगभग 6:00 बजे एक व्यक्ति ने उन्हें धारदार ब्लेड दिखाकर डराया-धमकाया और उनका मोबाइल लूटकर फरार हो गया। प्रार्थी की शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली कांकेर में अपराध क्रमांक 259/2026, धारा 309(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर प्रधान आरक्षक दिनेश कुलदीप के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टिकरापारा बस्ती, मेलाभाठा क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी शिवा वाल्मीकि (28 वर्ष, निवासी टिकरापारा कांकेर) को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद लूटा हुआ मोबाइल जब्त कर लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी शिवा वाल्मीकि थाना कांकेर का आदतन अपराधी है और पुलिस की गुंडा-बदमाश सूची में शामिल है।

उसके खिलाफ चोरी, नकबजनी, लूट, आर्म्स एक्ट और राज्य सुरक्षा अधिनियम सहित कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं।

आरोपी को 4 अगस्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस त्वरित और सफल कार्रवाई में निरीक्षक जितेन्द्र साहू, प्रधान आरक्षक दिनेश कुलदीप, प्रधान आरक्षक कौशल साहू, आरक्षक रोशन राठौर, आरक्षक ईश्वर साहू एवं आरक्षक रोमेश दीवान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

15 अगस्त तक सर्वे पूरा करने के निर्देश, 3 लाख से कम आय वाले जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता

2017 से पहले सरकारी जमीन पर बसे पात्र परिवारों को मिलेगा पट्टा, रायगढ़ जिले में सर्वे शुरू

रायगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ शासन ने शहरी क्षेत्रों में वर्षों से सरकारी भूमि पर निवास कर रहे जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। शासन के निर्देश पर वर्ष 2017 से पहले से सरकारी भूमि पर निवासरत पात्र परिवारों को भूमि का पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में रायगढ़ जिले में भी सर्वे कार्य शुरू हो गया है। राजस्व विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए 15 अगस्त 2026 तक सर्वे कार्य पूर्ण करने के लिए कहा है, ताकि पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर आगे की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जा सके। शासन के निर्देशानुसार सर्वे का कार्य नगरीय निकायों और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा। सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित परिवार वर्ष 2017 से पहले से सरकारी भूमि पर निवास कर रहा है तथा शासन द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है। सर्वे रिपोर्ट संचालक भू-अभिलेख को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर पात्र हितग्राहियों का अंतिम चयन कर उन्हें पट्टा प्रदान किया जाएगा।योजना के तहत नगर निगम क्षेत्रों में अधिकतम 600 वर्गफीट तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में अधिकतम 800 वर्गफीट भूमि पर कब्जा रखने वाले परिवारों को ही पात्र माना जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा और ऐसे मामलों में पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा। शासन की मंशा वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को भूमि पर वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना है, न कि बड़े पैमाने पर किए गए अतिक्रमण को वैध करना।शासन की नीति के अनुसार पात्र हितग्राहियों को प्रारंभिक रूप से 30 वर्षों के लिए पट्टा जारी किया जाएगा। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद नियमानुसार इसका नवीनीकरण भी कराया जा सकेगा। इससे वर्षों से सरकारी भूमि पर रह रहे परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिलने के साथ-साथ विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सुविधा होगी।

पात्रता के मापदंड तय

शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कब्जाधारी इस योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा। जिन लोगों के पास पहले से स्वयं का मकान उपलब्ध है, तालाब, नाले, ग्रीन बेल्ट अथवा फुटपाथ पर अतिक्रमण किया गया है या जिनका कब्जा सार्वजनिक विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उन्हें योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। जिन हितग्राहियों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है तथा जो अपने निवास संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिलेगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति ने निवास के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य अथवा व्यावसायिक व्यवस्था के लिए सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, तो उसे पट्टा वितरण के लिए अमान्य माना जाएगा। क्या कहते है एसडी ?म. महेश शर्मा =2017 से पहले जिन लोगों का नजूल भूमि पर कब्जा है।उनका सर्वे कर पट्टा प्रदान किया जाएगा।नगर निगम क्षेत्र में 6 सौ स्क्वायर फीट एवं नगर पालिका क्षेत्र में 8 सौ स्क्वायर फीट कब्जे की भूमि ही पट्टा वितरण के लिए मान्य होगा।

संपादकीय

हाईवे बढ़े, हादसे भी बढ़े- 2025 में 5.13 लाख सड़क दुर्घटनाएं

सरकार अब ईंधन की खपत और वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन सड़क हादसों के मूल प्रश्न पर ध्यान कम ही दिया जा रहा है।दुर्घटनाओं के इन आंकड़ों से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण ही प्राथमिकता है, सुरक्षा के पहलू का उसके लिए कोई महत्त्व नहीं है? सड़क एवं परिवहन सुविधाओं का विकास किसी भी देश की प्रगति, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक उत्थान की रीढ़ होता है। व्यापार को गति देने, दूरदराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने और आम जनजीवन को सरल बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। भारत में भी नई सड़कों के निर्माण और पहले से बने मार्गों के चौड़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि विकास के इस पथ पर सुरक्षित सफर की प्रतिबद्धता पीछे क्यों छूटती जा रही है?एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में सड़क दुर्घटनाएं साल-दर-साल बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बीते गुरुवार को लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए गए, वे स्थिति के भयावह होने की ओर इशारा करते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, देश में वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में 5.3 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 5.13 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिनमें 1.83 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई।दुर्घटनाओं के इन आंकड़ों से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण ही प्राथमिकता है, सुरक्षा के पहलू का उसके लिए कोई महत्त्व नहीं है? कहने को सरकार की ओर से सड़क हादसों को कम करने के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम और विशेष अभियान शुरू किए गए हैं, फिर क्या वजह है कि सड़कों पर लोगों की जान जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है!पिछले वर्ष देश में वाहनों की तेज रफ्तार के कारण सबसे ज्यादा 82 हजार से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो कुल सड़क हादसों का लगभग सोलह फीसद है। इस मामले में देखा जाए, तो राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्र की सड़कों पर जगह-जगह वाहनों की गति मापने के लिए सीसीटीवी और दूसरे यंत्र लगाए गए हैं। ऐसे में अगर आज भी सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं वाहनों की तेज गति के कारण ही हो रही हैं, इसे किस तरह देखा जाएगा। जाहिर है कि जब किसी व्यवस्था की सही तरीके से निगरानी, देखरेख और उसके आधार पर ईमानदारी से सुधार की दिशा में कार्य नहीं होगा, तो सकारात्मक नतीजे की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है!सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि गलत दिशा में वाहन चलाने और लेन के नियमों का पालन न करने के कारण पिछले वर्ष करीब चार हजार सड़क दुर्घटनाएं हुईं।

आंदोलन की संस्कृति: अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी आवश्यक

(ललित गर्ग)

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संवाद, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं का जीवंत तंत्र है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार प्राप्त है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार कभी भी हिंसा, अराजकता, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश या सुरक्षा बलों पर हमले का लाइसेंस नहीं बन सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह विरोध को भी सम्मान देता है, किंतु विरोध की भी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन की संस्कृति पर पुनर्विचार किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की ऐसी परंपरा विकसित की थी, जिसमें नैतिक बल सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह में विरोध था, परंतु वैमनस्य नहीं। संघर्ष था, परंतु हिंसा नहीं। दृढ़ता थी, परंतु अराजकता नहीं।

भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संवाद, असहमति और संवैधानिक मर्यादाओं का जीवंत तंत्र है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी मांगों और विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार प्राप्त है। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार कभी भी हिंसा, अराजकता, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश या सुरक्षा बलों पर हमले का लाइसेंस नहीं बन सकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह विरोध को भी सम्मान देता है, किंतु विरोध की भी अपनी सीमाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। हाल के वर्षों में कुछ आंदोलनों ने यह गंभीर प्रश्न खड़ा किया है कि क्या लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में कानून और व्यवस्था को चुनौती देना स्वीकार्य हो सकता है? यदि कोई प्रदर्शन बैरिकेड तोड़ने, पुलिस पर हमला करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थान की ओर जबरन बढ़ने का प्रयास करे, तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे केवल मूकदर्शक बनी रहें। राज्य का पहला दायित्व नागरिकों की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैलेट गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए यह कहना कि असाधारण परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसी संतुलित दृष्टिकोण का परिचायक है। न्यायालय ने किसी भी प्रकार के असीमित बल प्रयोग को उचित नहीं ठहराया, बल्कि यह स्पष्ट संकेत दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के पास आवश्यक साधन भी होने चाहिए। यदि सुरक्षा बलों से हर प्रभावी उपाय छीन लिया जाएगा, तो हिंसक भीड़ पर नियंत्रण कैसे स्थापित होगा? यह प्रश्न केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को असीमित अधिकार मिल जाने चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा और जवाबदेही के दायरे में रहती है। यदि कहीं बल प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ हो, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जांच का आधार तथ्य होने चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं। जिस प्रकार प्रदर्शनकारियों की पीड़ा सुनी जानी चाहिए, उसी प्रकार घायल हुए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों का पक्ष भी उतनी ही गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन की संस्कृति पर पुनर्विचार किया जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की ऐसी परंपरा विकसित की थी, जिसमें नैतिक बल सबसे बड़ा हथियार था। सत्याग्रह में विरोध था, परंतु वैमनस्य नहीं। संघर्ष था, परंतु हिंसा नहीं। दृढ़ता थी, परंतु अराजकता नहीं। दुर्भाग्य से आज कुछ आंदोलनों में संवाद की जगह टकराव, संयम की जगह उग्रता और तर्क की जगह भीड़ की शक्ति को महत्व दिया जाने लगा है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में परिवर्तन सड़क पर पत्थर फेंकने से नहीं, बल्कि विचार, संगठन, जनजागरण और संवैधानिक प्रक्रियाओं से आता है। यदि हर असहमति हिंसक रूप ले लेगी, तो सबसे अधिक नुकसान उन्हीं युवाओं का होगा, जिनके भविष्य के नाम पर आंदोलन किए जाते हैं। लोकतंत्र की रक्षा भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुशासन और उत्तरदायित्व से होती है।

यदि यह मान लिया जाए कि किसी राजनीतिक दल या उसके समर्थकों द्वारा आयोजित आंदोलन में कुछ असामाजिक और हिंसक तत्वों ने प्रवेश कर उसे अराजक दिशा देने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में सरकार का प्राथमिक दायित्व कानून-व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। समय रहते प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई, भले ही

उससे कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हों, व्यापक अराजकता और राष्ट्रीय संस्थानों को संभावित क्षति से बचाने के उद्देश्य से देखी जा सकती है। साथ ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह भी अपेक्षित है कि विपक्ष जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंसा और तोड़फोड़ से स्पष्ट दूरी बनाए तथा वैध मांगों के समर्थन और अवैध कृत्यों के विरोध के बीच स्पष्ट रेखा खींचे। लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होता है जब सरकार कानून के शासन का पालन करे, विपक्ष जिम्मेदार आचरण करे और आंदोलन संविधान की मर्यादाओं एवं शांतिपूर्ण तरीकों के भीतर संचालित हों।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी दल का यह दायित्व है कि वह जनभावनाओं को सकारात्मक दिशा दे। यदि कोई राजनीतिक संगठन या उसके समर्थक आंदोलन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ या कानून हाथ में लेने को प्रोत्साहित करते हैं, तो उसकी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। विपक्ष लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है, लेकिन उसका धर्म केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना भी है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा जनआंदोलनों का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, तो अंततः लोकतंत्र ही कमजोर होता है। सरकारों को भी यह आत्ममंथन करना चाहिए कि जनआक्रोश की स्थितियां क्यों बनती हैं। संवाद के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। पारदर्शी निर्णय, समय पर संवाद और शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था अनेक आंदोलनों को उग्र होने से पहले ही शांत कर सकती है। लोकतंत्र में शासन का अर्थ केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि विश्वास अर्जित करना भी है।

भविष्य के लिए कुछ स्पष्ट सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रत्येक बड़े आंदोलन के लिए पूर्व अनुमति, निर्धारित मार्ग, आयोजकों की स्पष्ट जवाबदेही, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा की स्थिति में त्वरित पहचान और दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही पुलिस को भी भीड़ नियंत्रण के आधुनिक, वैज्ञानिक और न्यूनतम आवश्यक बल के सिद्धांतों पर निरंतर प्रशिक्षित किया जाए। इससे नागरिक अधिकारों और कानून-व्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन स्थापित होगा। लोकतंत्र का सौंदर्य इस बात में नहीं कि कितनी जोर से नारे लगाए गए, बल्कि इस बात में है कि कितनी गंभीरता से संवाद हुआ। संसद जनता की आकांक्षाओं का मंदिर है। यदि कोई समूह अपनी बात संसद तक पहुंचाना चाहता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन संसद पर दबाव बनाने या उसे घेरने की संस्कृति लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करती है। लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है, भीड़तंत्र नहीं।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ-साथ विश्वगुरु बनने की दिशा में भी अग्रसर है। ऐसे समय में हमें विरोध की भी ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी जो विश्व के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करे। हमारे आंदोलन व्यवस्था को तोड़ने के नहीं, व्यवस्था को बेहतर बनाने के माध्यम बनें। हमारे प्रदर्शन राष्ट्र को विभाजित करने के नहीं, लोकतांत्रिक चेतना को समृद्ध करने के साधन बनें। अंततः यह स्मरण रखना होगा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब कर्तव्यों का भी समान रूप से पालन किया जाए। यदि आंदोलन संविधान की मर्यादाओं में रहकर होंगे, तो सरकार भी अधिक उत्तरदायी बनेगी और लोकतंत्र भी अधिक सशक्त होगा। भारत को ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता है जो व्यवस्था को चुनौती देने के बजाय उसे सुधारने की प्रेरणा दें। जो युवाओं को उग्रता नहीं, उत्तरदायित्व सिखाएं और जो राष्ट्रहित को दलगत हितों से ऊपर रखकर लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व, अनुशासित तथा जनोन्मुख बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।

स्विट्जरलैंड का 'टाइम बैंक'- जहां सेवा बनती है भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी

(अमिताभ स.)

अगर किसी मजबूरी की स्थिति में कभी उसे अपनी देखभाल करवाने की जरूरत पड़े, तो वह अपने कार्ड के जरिए सेवा का समय और अर्जित ब्याज निकाल सकता है। सुना-पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड में पेंशन बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए वहां बुजुर्गों को आखिरी दम तक भोजन और निवास की चिंता नहीं सताती। फिर भी, वहां कई लोग परोपकार के काम में जुटे हैं ङ्क अस्सी की उम्र पार किसी वृद्ध की देखभाल करने जैसे। वहां ऐसे काम पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपना आज का समय 'टाइम बैंक' में जमा करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि जब आज दूसरे की सेवा करने वाला बुजुर्ग होकर खुद असहाय होगा, चल-फिर नहीं सकेगा, तब वह अपने 'टाइम बैंक' में जमा सेवा के समय को निकालकर अपने लिए इस्तेमाल करवा सकता है।'टाइम बैंक' की व्यवस्था स्विट्जरलैंड के सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजना है। लोग अपनी युवावस्था में बुजुर्गों की सेवा करके अपना 'समय' जमा करते हैं और जब वे स्वयं बूढ़े, बीमार या असहाय हो जाते हैं, तब उस समय को अपने लिए निकलवा कर निशुल्क उपयोग करते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति का सेहतमंद, मिलनसार और दयालु होना लाजिमी है। उनकी सेवा के घंटों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत व्यक्तिगत 'टाइम अकाउंट' में जमा किया जाता है।

इस प्रक्रिया में अपना पेशा और काम-धंधा छोड़कर, दफ्तर की ड्यूटी की तरह या नर्सिंग पेशे की तरह बुजुर्ग की सेवा नहीं करनी होती। हर हफ्ते केवल दो बार, दो-दो घंटे के लिए ही मदद की जाती है। बाजार ले जाकर खरीदारी करवाना, उनका कमरा साफ करना, बाग में टहलाना और समय बचे तो बातचीत करना। सेवा समझौते के मुताबिक, एक साल बाद 'टाइम बैंक' हर मददगार के कुल कार्य घंटों की गणना करता है। उसी के आधार पर उन्हें टाइम बैंक कार्ड जारी किया जाता है।

अगर किसी मजबूरी की स्थिति में कभी उसे अपनी देखभाल करवाने की जरूरत पड़े, तो वह अपने कार्ड के जरिए सेवा का समय और अर्जित ब्याज निकाल सकता है। खाते की जांच कर टाइम बैंक कार्यालय किसी स्वयंसेवक को सहायता के इच्छुक व्यक्ति के घर या अस्पताल भेज देता है।

बेशक यह नई सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है, लेकिन सेवा की ऐसी परिकल्पना सभी देशों में लागू हो, तो कितना अच्छा हो। खासतौर पर भारत जैसे देशों में, जहां ज्यादातर युवा अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद में दूसरे शहरों और देशों में हमेशा के लिए चले जाते हैं और उनके बुजुर्ग माता-पिता अकेला जीवन जीने को विवश हैं।

हालांकि यह अपने आप में एक त्रासद विडंबना है कि जो माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, अपना सुख, संतोष और खुशी बच्चों के हित के अनुकूल बनाकर इसी को अपना भाग्य मान लेते हैं, उन्हें जीवन की सांध्यवेला में अपने भरोसे छोड़ दिया जाता है।

इसके बावजूद यही माना जाता है कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों में 'सेवा का मेवा' की कहानी सदियों से रची-बसी है। विचारक जैक कैनफील्ड का कथन इसी सेवा के काम को उजागर करता है कि आपकी मौजूदा आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। अपने माता-पिता, गुरुजन और बुजुर्ग परिजनों की सेवा करना शुरू से परम धर्म माना जाता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य 'स्वयं से पहले सेवा' भी मानव सेवा के भाव का संचार करता है।

कहते भी हैं कि किसी भी पेशे में जाने या अपनाने से पहले नेक इंसान बनना जरूरी है। मानव सेवा से बड़ा कोई कर्म और धर्म नहीं है। इसीलिए हमारे पौराणिक ग्रंथ भी 'मानव धर्म सर्वोपरि' के पाठ को जीवन में उतारने की सलाह देते हैं। मानव मात्र की सेवा करने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति और अनुभूति होती है, असीम सुख और सुकून मिलता है। मनोविज्ञान भी मानता है कि अगर खुशी, समृद्धि और संतोष जैसे गुणों को जीवन में लाना है, तो सेवा को अपने जीवन में जोड़ना जरूरी है। यानी हरेक का पहला धर्म, पहली काबिलियत और पहली अहमियत मददगार इंसान बनना होनी चाहिए।

सबके प्रति सेवा भाव रखने वालों का सबसे अच्छा साथी उनका अंतर्मन होता है, जो खुद की अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झकझोरता है। सवाल है कि इसके बावजूद ऐसा कैसे हो रहा है कि समाज में आपसी दूरियां बढ़ती जा रही हैं और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इसका साधारण-सा जवाब हो सकता है कि हम अपने आसपास के संवेदनशील लोगों को गले लगाएं और अपना कदम आगे बढ़ाकर दूसरों के पास जाएं। उनकी दिक्कत जानने-समझने और फिर उसका समाधान ढूंढ़ने की कोशिश करें।

परमाणु आत्मनिर्भरता- भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत और वैश्विक नेतृत्व की नई नींव

(विजन कुमार पांडेय)

यह प्रश्न इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही। दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन, उन्नत उपकरणों और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच लगभग बंद हो गई।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का भी आधार बन चुकी है। बदलती वैश्विक राजनीति, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति शृंखलाओं पर बढ़ती निर्भरता ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन देशों के पास अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता है, वही भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले सात दशकों में ऐसी ही क्षमता विकसित की है। मगर प्रश्न यह है कि क्या देश अपनी इस उपलब्धि को नीति-निर्माण के केंद्र में रख पा रहा है या विदेशी तकनीक का आकर्षण अभी भी स्वदेशी आत्मविश्वास पर भारी पड़ रहा है?

यह प्रश्न इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही। दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन, उन्नत उपकरणों और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच लगभग बंद हो गई।

उस समय यह माना गया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय तक पिछड़ जाएगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा आयोग और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक और निजी उद्योगों के सहयोग से धीरे-धीरे ऐसी तकनीक विकसित की, जिसने विदेशी निर्भरता को काफी हद तक समाप्त कर दिया। रिएक्टरों के डिजाइन से लेकर भारी उपकरणों, नियंत्रण प्रणालियों और सुरक्षा तंत्र तक भारत ने अपनी क्षमता विकसित की।

वर्ष 2008 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते ने भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान दिलाया और यूरेनियम आयात का मार्ग खोला। इससे उन परमाणु बिजलीघरों को राहत मिली जो ईंधन की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। मगर इस समझौते की एक ऐसी व्याख्या भी सामने आई, जिसमें यह मान लिया गया कि अब भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी परमाणु संयंत्रों और तकनीकों पर निर्भर होना चाहिए।

सवाल है कि किसी देश ने कठिन परिस्थितियों में विश्वस्तरीय घरेलू तकनीक विकसित कर ली हो, तो क्या उसकी प्राथमिकता उसी क्षमता का विस्तार नहीं होनी चाहिए। भारत के स्वदेशी 'प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर' आज विश्व के सबसे किफायती परमाणु संयंत्रों में गिने जाते हैं। देश 700 मेगावाट क्षमता वाले आधुनिक रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है और आगे उनकी संख्या बढ़ाने की योजना भी है।

ऊर्जा क्षेत्र में लागत का बहुत महत्त्व होता है। किसी परियोजना की व्यावहारिकता केवल उसकी तकनीकी श्रेष्ठता से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह कितनी किफायती है और उसके संचालन पर भविष्य में कितना व्यय होगा। यदि भारत कम लागत में सुरक्षित और विश्वसनीय परमाणु संयंत्र बना सकता है, तो यह केवल घरेलू आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक अवसर भी है।

आने वाले वर्षों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों को स्वच्छ और निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भारत उनके लिए एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार बन सकता है।

इसी संदर्भ में हाल में तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े दस्तावेजों के कथित डेटा लीक की घटना ने एक नया सवाल खड़ा किया है। हालांकि सरकारी एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि परमाणु संयंत्र के संचालन तंत्र, रिएक्टर नियंत्रण प्रणाली या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई संवेदनशील सूचना प्रभावित नहीं हुई। फिर भी यह घटना इसका संकेत देती है कि परमाणु क्षेत्र की सुरक्षा अब केवल ऊंची दीवारों, कड़े पहरे और बहुस्तरीय भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गई है।

वास्तव में, परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल स्वदेशी तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि उस तकनीक पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना भी है। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दूरसंचार की तरह परमाणु प्रौद्योगिकी भी अब भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्त्वपूर्ण आधार बन चुकी है। ऐसे में यदि भारत अपनी मूलभूत ऊर्जा संरचना के लिए अत्यधिक विदेशी तकनीक या उपकरणों पर निर्भर रहता है, तो भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय तनाव का प्रभाव उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है।

भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने अपनी परमाणु क्षमता को वैज्ञानिक अनुसंधान और घरेलू औद्योगिक सहयोग के आधार पर विकसित किया है। यही कारण है कि भारतीय परमाणु संयंत्रों की निर्माण लागत विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम मानी जाती है। लागत में यह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त केवल आर्थिक लाभ नहीं देती, बल्कि भारत को वैश्विक बाजार में भी अलग पहचान प्रदान करती है।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देश स्वच्छ तथा निरंतर ऊर्जा की तलाश में हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के महंगे परमाणु संयंत्र उनके लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं हैं। भारत यदि अपनी तकनीक, निर्माण क्षमता और प्रशिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से विकसित करे, तो वह इन देशों का भरोसेमंद साझेदार बन सकता है।

भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं। यदि तीसरे चरण के परमाणु कार्यक्रम को अपेक्षित गति मिलती है, तो भारत न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिक सुरक्षित ढंग से पूरा कर सकेगा, बल्कि भविष्य की परमाणु प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा, आधुनिक विज्ञान साझेदारी और ज्ञान-विनिमय से आगे बढ़ता है। इसलिए जहां नई तकनीकों, सुरक्षा मानकों और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग भारत की क्षमता को मजबूत करता हो, वहां उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

सरकार को इस दिशा में तीन स्तरों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला, स्वदेशी परमाणु उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को दीर्घकालीन वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन दिया जाए, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकें। दूसरा, परमाणु क्षेत्र की साइबर सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला और डिजिटल संरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे कुडनकुलम जैसी घटनाओं से मिलने वाले सबक भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकें। तीसरा, भारतीय परमाणु तकनीक को वैश्विक स्तर पर निर्यात योग्य बनाने के लिए कूटनीतिक, वित्तीय और औद्योगिक रणनीति तैयार की जाए। जिन परिस्थितियों में दुनिया ने भारत को तकनीकी रूप से अलग-थलग करने का प्रयास किया, उन्हीं परिस्थितियों में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं ने आत्मनिर्भरता की ऐसी नींव रखी, जो आज देश की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी बन चुकी है। ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भारत के सामने चुनौती नई तकनीक खोजने की नहीं, बल्कि अपनी विकसित क्षमता पर विश्वास करने की है। परमाणु आत्मनिर्भरता की वास्तविक परीक्षा यही है कि वह अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को केवल गर्व का विषय न बनाए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय विकास और वैश्विक नेतृत्व का आधार भी बनाए।

सड़क सुरक्षा के लिए रायगढ़ ट्रैफिक पुलिस का अभिनव अभियान, सड़क किनारे पेड़ों पर लगाए जा रहे Tree Marker रेडियम रिफ्लेक्टर, रात में दुर्घटनाओं की आशंका होगी कम

एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिलेभर में लगातार चल रहा सुरक्षा अभियान

रायगढ़ /मूक पत्रिका

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में एक अभिनव सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। एडिशनल एसपी अनिल सोनी एवं एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) श्री पुष्पेन्द्र बघेल के मार्गदर्शन तथा ट्रैफिक डीएसपी श्री उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीमों द्वारा मुख्य मार्गों पर सड़क किनारे स्थित वृक्षों पर ञ्जह्लद्गद्ग स्ड्डह्लद्मद्गह्ल रेडियम रिफ्लेक्टर स्टीकर लगाए जा रहे हैं। अक्सर रात्रि के समय सड़क किनारे खड़े पेड़ अंधेरे में स्पष्ट दिखाई नहीं देते, जिससे तेज रफ्तार या विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों के चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसी जोखिम को कम करने के लिए यातायात पुलिस ने जिले के विभिन्न मार्गों का सर्वे कर ऐसे चिन्हित वृक्षों पर उच्च गुणवत्ता

वाले रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जो वाहन की हेडलाइट पड़ते ही दूर से चमकते हैं और चालक को पहले से सतर्क कर देते हैं। यह छोटा लेकिन प्रभावी प्रयास विशेष रूप से रात के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान के लिए थाना यातायात की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो जिले के विभिन्न मार्गों पर लगातार कार्य कर रही हैं। अभियान के तहत कल उर्दना-गेरवानी-लाखा मार्ग, पहाड़ मंदिर-बनोरा मार्ग तथा इंदिरा विहार-हमीरपुर मार्ग में सड़क किनारे चिन्हित पेड़ों पर ञ्जह्लद्गद्ग स्ड्डह्लद्मद्गह्ल, रेडियम रिफ्लेक्टर स्टीकर लगाए गए। आगामी दिनों में जिले के अन्य संवेदनशील एवं दुर्घटना संभावित मार्गों पर भी यह कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे रात्रि में निर्धारित गति सीमा का पालन करें, हाई बीम का अनावश्यक उपयोग न करें, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सड़क संकेतकों एवं रिफ्लेक्टर मार्किंग का सम्मान करते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

'प्रतिभा को पंख' टैलेंट तिहार में बच्चों ने दिखाई कला और हुनर, नृत्य-गायन से बांधा समां

बस्तर /मूक पत्रिका

पवन कुमार- विकासखंड बस्तर के संकुल केंद्र लामकेर एवं सालेमेटा-02 के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को संकुल भवन लामकेर में संकुल स्तरीय टैलेंट तिहार 'प्रतिभा को पंख' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन, चित्रकला, वाद्य यंत्र वादन एवं एकांकी नाटक जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। एकल नृत्य में धनेश्वरी एवं आनंदी बघेल, सामूहिक नृत्य में लविना एवं साथी, पायल एवं साथी तथा माध्यमिक वर्ग में गुड़िया एवं साथी की प्रस्तुतियों ने खूब तालियां बटोरी। वहीं एकल गायन में कांची भोयर, सामूहिक गायन में पायल एवं साथी, वाद्य यंत्र वादन में उमेश कश्यप तथा चित्रकला में नरेंद्र कश्यप एवं ललित भद्रे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच का विकास करना था। आयोजन संकुल समन्वयक धर्मेंद्र कुमार अग्रवानी एवं संतोष अग्रवानी के नेतृत्व में संपन्न हुआ।कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक राकेश शर्मा, ईश्वर लाल बंजारे, सुनील कुमार मरावी, टेक राम, देव कुमार नाग, कामेश कुमार, मोसू राम सार्दुल, अर्जुन सिंह कोमरा, संगीता शोरी, ललिता धामगए, नेहा कश्यप, गौरी, रामेश्वरी ठाकुर, पार्वती ध्रुव, उमा राज एवं विमला पाण्डेय सहित दोनों संकुलों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। समापन पर सभी प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई।

स्टे के बावजूद हो रहा जमीन पर अवैध कब्जा, संगीतराई में सरकारी जमीन हथियाने में महिलाएं भी पीछे नहीं

रायगढ़/मूक पत्रिका

शहर से लगे सांगीतराई क्षेत्र में चल रहे अवैध कब्जे के एक प्रकरण में स्टे के बावजूद भी काम जारी हैं। बता दें की ग्राम सांगीतराई की सरपंच नें तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया की गांव में सडक़ व शेड निर्माण के लिए प्रस्तावित सरकारी जमीन पर छातामुड़ा की महिला अवैध रूप से बाउंड्री वाल निर्माण के लिए नींव खोदी जा रही हैं। शहर से लगे हुए सांगीतराई में शासकीय जमीन पर हो रहे कब्जे की शिकायत जब सरपंच द्वारा की गई तो इसपर राजस्व विभाग नें तत्काल संज्ञान में लिया और लालदेवी को जमीन संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ तहसील

न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश जारी किए साथ ही शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए न्यायालय नें आगामी पेशी तक उक्त जमीन पर किसी भी तरह के कार्य किए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।3 अगस्त को तहसील न्यायालय से यह आदेश पारित हुआ और अगले ही दिन 4 अगस्त को महिला द्वारा पुनः उक्त शासकीय भूमि पर जेसीबी लगवाकर नींव खुदाई का काम चालू कर दिया गया। सांगीतराई क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जे का यह कोई पहला मामला नहीं हैं। इस क्षेत्र में सक्रिय भू माफ्यिाओ नें सरकारी जमीन में कब्जे के साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने मेंं भी महारत हासिल की हैं। इस मामले में भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए काम जारी रखा गया हैं। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग इस मामले में क्या रुख अख्तियार करता हैं। कोर्ट में प्रकरण लंबित होने और स्टे जारी होने के बाद भी सरकारी जमीन पर काम बेखौफ जारी हैं इससे एक बात तो साफ हैं कि भू माफ्यिाओ को किसी भी तरह का डर नहीं हैं।

भारतमाला प्रोजेक्ट के ड्रोन सर्वे वीडियो में एलाइनमेंट विवाद की परतें खुलीं!

दूसरी जांच रिपोर्ट में कई चौकाने वाले तथ्य उजागर

धरमजयगढ़/मूक पत्रिका

जिले में भारतमाला सडक़ परियोजना के अंतर्गत धरमजयगढ़ क्षेत्र के सिसरिंगा घाट में सडक़ निर्माण को लेकर उठे गंभीर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। प्रारंभिक जांच के बाद दोबारा कराई गई विभागीय जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आने की चर्चा है, जिनसे परियोजना के क्रियान्वयन और एलाइनमेंट में हुए कथित बदलाव पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, पहले चरण की जांच में निर्माण एजेंसी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को राहत मिली थी। इसके बाद राइट ऑफ वे की वास्तविक स्थिति से जुड़े डिजिटल फोटो, तकनीकी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य संबंधित अधिकारियों तक

पहुंचे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर धरमजयगढ़ वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रकरण की पुनः जांच कराई गई। विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि दूसरी जांच के दौरान यह पाया गया कि सडक़ निर्माण के दौरान प्रभावित प्राचीन मंदिर परिसर की संरचनाओं को क्षति पहुंची। जांच अधिकारी ने कथित तौर पर यह भी बताया कि निर्माण एजेंसी मंदिर परिसर में क्षतिग्रस्त संपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए सहमत हुई है। जांच के दौरान वन अधिकार पट्टा भूमि के उपयोग का मुद्दा भी सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, मंदिर के पुजारी को आवंटित वन अधिकार पट्टा भूमि का परियोजना कार्य में उपयोग किए जाने के संबंध में कंपनी और पट्टाधारी के बीच एक समझौता हुआ था। बताया जा रहा है है कि इसके एवज में लगभग पांच लाख रुपये का भुगतान किया गया।मामले का तकनीकी पक्ष भी चर्चा में है। ड्रोन सर्वे के आधार पर यह तथ्य सामने आ रहा है कि प्रस्तावित मार्ग के समीप स्थित उच्च दाब विद्युत टावर को स्थानांतरित करने से बचने के लिए सडक़ के एलाइनमेंट में बदलाव किया गया। आरोप है कि इसी परिवर्तन के कारण मंदिर परिसर और आसपास की वन संपदा प्रभावित हुई। यदि जांच में यह तथ्य प्रमाणित होते हैं, तो परियोजना के क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं।इस संबंध में जब धरमजयगढ़ वनमंडलाधिकारी जितेन्द्र कुमार उपाध्याय से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, उनकी ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। धरमजयगढ़ डी एफ ओ का विस्तृत पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। अब स्थानीय ग्रामीणों, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और प्रशासनिक हलकों की नजर इस बात पर है कि पुनः जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग निर्माण एजेंसी और अन्य जिम्मेदार पक्षों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। यह पूरा मामला भारतमाला परियोजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, वन संरक्षण और सार्वजनिक जवाबदेही की कसौटी बनता जा रहा है।

पीएम मत्स्य संपदा योजना से मछुआरों को मिलेगा निशुल्क बीमा, आर्थिक सहायता और अनुदान

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। प्रभारी अधिकारी एन पी ओगरे से प्राप्त जानकारी अनुसार, इस योजना में सामान्य वर्ग के लिए प्रोजेक्ट लागत का 40त्न और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग और महिलाओं के लिए प्रोजेक्ट लागत का 60त्न तक की वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसमें मत्स्य पालकों को 5 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा, आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख, तथा अस्पताल के खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना मत्स्य पालकों और उनके परिवारों के लिए कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य देश में नीली क्रांति लाना,मछली और मछली पकड़ने वाले किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एक मजबूत मत्स्यिकी प्रबंधन और लिमिटेड ढांचा तैयार करना है। मछली उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक तकनीक अपनाना और मछुआरों की आय को बढ़ाना, मछली उत्पादन को बढ़ाना, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे (कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट) में सुधार करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। साथ ही मछुआरों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और वित्तीय सहायता तथा सब्सिडी भी शामिल है।

बीमा मत्स्य पालक परिवारों के लिए है सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के सहयोग से गो-डिजिट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा दावों का भुगतान किया जाता है। योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमित मत्स्य पालक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, स्थायी अथवा अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपए तथा दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर 25 हजार रुपए तक की सहायता राशि बीमित व्यक्ति अथवा उसके नामिनी को प्रदान की जाती है। मत्स्य पालन विभाग ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों को आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके जीवन-यापन को सहारा देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य पालकों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार मिल रहा है, जिससे वे अधिक विश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़ रहे हैं।

पूर्व सरपंच ने कलेक्टर से लगाई गुहार,12 लाख की लागत से हुआ था निर्माण सड़क निर्माण कार्य के 7.20 लाख रुपये भुगतान की रखी मांग

रायगढ़/मूक पत्रिका

जनपद पंचायत पुसौर अंतर्गत ग्राम पंचायत रनभाटा की पूर्व सरपंच ममता छत्तर ने कलेक्टर रायगढ़ को आवेदन सौंपकर वर्ष 2024-25 में कराए गए सड़क निर्माण कार्य की शेष देय राशि का भुगतान कराने की मांग की है। पूर्व सरपंच का आरोप है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने और मूल्यांकन होने के बावजूद संबंधित ठेकेदार (वेंडर) को अब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे आर्थिक परेशानी की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब हो कि रनभाटा के पूर्व सरपंच द्वारा सौंपे गए आवेदन के अनुसार, वर्ष 2024-25 में एसटीजीसी (स्ञ्जत्रष्ट) मद के तहत आदिवासी मोहल्ला में सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली थी। इस कार्य के लिए 12 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई

थी। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा इसका 12 लाख 198 रुपये का मूल्यांकन किया गया। इसमें प्रथम किस्त के रूप में 4 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 7 लाख 20 हजार रुपये की अंतिम राशि अब तक लंबित बताई गई है।पूर्व सरपंच ममता छत्तर ने आवेदन में उल्लेख किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान सड़क निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूरा कराया गया था। निर्माण कार्य का संपूर्ण विवरण ग्राम पंचायत रनमांगटा के मस्टर रोल एवं पंजी क्रमांक 3780 में दर्ज है। उन्होंने दावा किया है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अंतिम किस्त की राशि पंचायत के खाते में जमा भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित वेंडर को भुगतान नहीं किया गया।जबकि भुगतान के लिए आवश्यक मूल देयक 10 जून 2026 को ग्राम पंचायत सचिव को प्रस्तुत कर दिए गए थे। इसके बाद भी भुगतान की कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने 6 जुलाई 2026 को कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पुसौर को भी शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सरपंच एवं सचिव से जवाब भी तलब किया गया। पूर्व सरपंच का आरोप है कि जवाब में नव-निर्वाचित सरपंच एवं सचिव ने अन्य वेंडर को भुगतान किए जाने की बात कही, जबकि उनके अनुसार संबंधित निर्माण कार्य का बिल एवं दस्तावेज उनके हस्ताक्षर से प्रस्तुत किए गए थे, जिसके प्रमाण भी आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं।

बकाया राशि भुगतान की मांग-पूर्व सरपंच ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सड़क निर्माण कार्य में सामग्री उपलब्ध कराने वाले संबंधित वेंडर को 7 लाख 20 हजार रुपये की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान कराया जाए, ताकि लंबे समय से लंबित भुगतान का विवाद समाप्त हो सके।

तोखन साहू, ओपी चौधरी, गुरु खुशवंत साहेब, सहित विधायकों सांसदों की रही उपस्थिति

हेल्पिंग हैंड्स क्लब का रक्तदान महाकुंभ से मिलेगी जरूरतमंद को मदद

खरसिया /मूक पत्रिका

मानवसेवा माधवसेवा के संकल्प के साथ कार्य करने वाली खरसिया से प्रारंभ हुई सामाजिक संस्था हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा भावी संस्था बन चुकी है। आज क्लब के द्वारा के मेकाहारा हॉस्पिटल में रक्तदान का महाकुंभ एवं छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद विजय बघेल, विधायक अनुज शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, ए आई जी संजय शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र नायक, डाक्टर विवेक केशरवानी, डॉक्टर जितेंद्र सराफएवं कई डॉक्टर्स कई पुलिस अधिकारीगण, कई सामाजिक संस्थाएं शामिल हुए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तत्पश्चात राज्यगीत हुआ स्वागत उद्बोधन रत्न सम्मान का सिलसिला दिनभर चलता रहा। मंचस अतिथि में हेल्पिंग हैंड्स क्लब

फाउंडेशन के प्रमुख मार्गदर्शक सुनील रामदास अग्रवाल, प्रदेश संरक्षक मनोज गोयल, रमेश अग्रवाल,प्रदेश अध्यक्ष अंकित अग्रवाल, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष बबीता अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति अग्रवाल, विन्नी सलूजा, सुनीता पांडे, उदित अग्रवाल, रजत अग्रवाल रहे। हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन द्वारा इस कार्यक्रम की तैयारी विगत कई दिनों से की जा रही थी जिसका परिणाम आज शानदार आयोजन के सफलता से हुआ। तोखन साहू ने अपने उद्बोधन में कहा ङ्क हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन द्वारा निरंतर ही रक्तदान पर्यावरण क्षेत्र में कार्य किया जाता है रक्तदान सबसे पुण्य का कार्य है हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन मानवसेवा माधवसेवा के संकल्प के साथ अतुलनीय कार्य पूरे देश में कर रहा है में संस्था के सभी युवा साथियों को माताओं को इस नेक कार्य के लिए नमन करता हु। ओपी चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा- करोना महामारी जैसी वैश्विक स्थिति में आपने अपनी संस्था की नींव रखी जो आज आप सब इतने विशाल वृक्ष के रूप में पूरे प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे है। आज मुझे यहां आकर बहुत ही सौभाग्यशाली प्रतीत हो रहा है रक्तदान महादान है जीवनदान है में अंकित अग्रवाल एवं उनके टिम के समस्त साथियों को बधाई देता हु। इस शानदार सफल आयोजन हेतु हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के संरक्षक मनोज गोयल एवं प्रदेश अध्यक्ष अंकित अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, जगमीत सिंह विन्नी सलूजा, उदित अग्रवाल, रजत अग्रवाल, सुनीता पांडे, ज्योति अग्रवाल ने सभी अतिथियों का एवं सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के कोर टिम से भारती मोदी, अल्पना शर्मा, विवेक श्रीवास्तव, अंकित चौधरी, विवेक सान्याल,अनामिका मिश्रा, अमित केडिया, वर्षा अग्रवाल, डिंपल झाझरिया, श्रुति श्रीवास्तव, पुष्पा लाहोटी, कोपल बोथवल, मयंक जैन, नमन अग्रवाल, रिद्धि अग्रवाल, अनुभव अग्रवाल, जसप्रीत कौर, सेजल खंडेलवाल, अनुष्का अग्रवाल,सुमित अग्रवाल,मनीष अग्रसल,राहुल अग्रवाल,नीलम अग्रवाल, काजल अग्रवाल, अविनाश बोस, सुजाता अग्रवाल,कशिश राजपूत, विशा, अनुष्का एवं नए सदस्य में दीपक अग्रवाल बिलासपुर की टिम एवं आशा अग्रवाल खरसिया की टिम सामिल रही।

संक्षिप्त समाचार

एआई बच्चों की कर रहा निगरानी, स्टार्टअप्स ला रहे स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम

न्यूयॉर्क, एजेंसी। बच्चों की देखभाल के लिए इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट बेबी मॉनिटर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार किए जा रहे हैं। नैनिट, बेबीटेक समेत कई स्टार्टअप ऐसे सिस्टम विकसित कर रहे हैं, जो रात के दौरान बच्चे की नींद, सांस, करवट और गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं। कंपनियां भविष्य में एआई के जरिए बच्चों की दिनभर की गतिविधियों, विकास और व्यवहार का भी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में काम कर रही हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे बेबी सर्विलांस का नया दौर मान रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दीवार पर लगा सफेद कैमरा बच्चों पर सीधा नजर रखता है। एचडी वीडियो ऐसे सर्वर पर भेजी जाती है, जहां मशीन-लर्निंग एल्गोरिद्म उसके हर हिलने-डुलने और उसकी आंखें खुलने-बंद होने के सटीक समय का रिकॉर्ड रखते हैं। इन आंकड़ों को चार्ट और विश्लेषण के रूप में तैयार करते हैं। इसमें सांस लेने से लेकर सोने में लगा समय, रात के माता-पिता की जरूरत कितनी बार पड़ी, ऐसी जानकारी रिकॉर्ड की जाती हैं। नैनिट का दावा है कि उसके 10 लाख सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और सालाना आय 10 करोड़ डॉलर से अधिक है। उसका सबसे महंगा किट 474 डॉलर (करीब 45 हजार रुपये) का है। नैनिट ने निवेशकों से हाल में 5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं।

अमेरिका में 80 वर्षीय अभिनेता विंसेंट पास्टर का शव बरामद, यूएई में इस साल पहली बार 50 डिग्री तापमान

वाशिंगटन, एजेंसी। द सोप्रानोस में सल्वाटोर बोनपेन्सिएरो की भूमिका के लिए प्रसिद्ध अभिनेता विंसेंट पास्टर का निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। उनके मैनेजर बॉब मैकगोवन ने बताया कि पास्टर न्यूयॉर्क के सिटी आइलैंड स्थित अपने घर में मृत पाए गए। पास्टर ने 1980 के दशक से फिल्मों में अभिनय शुरू किया था। उन्होंने 1990 की गुडफेलस और अवेकनिंग्स जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना में सेवा देने वाले पास्टर अपने दयालु और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार में उनकी बेटी रेनी पास्टर हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में इस साल पहली बार तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय मौसम केंद्र (एनसीएम) के अनुसार, रविवार को देश के एक आंतरिक क्षेत्र में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। यह इस वर्ष का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गर्मियों का चरम दौर अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है, लेकिन फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अगस्त के दौरान तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो सकती है, लेकिन तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस का असर कई सप्ताह तक बना रहेगा। यूएई में आमतौर पर अक्तूबर के मध्य से मौसम में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलता है। तब तक दिन के समय अत्यधिक गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाती रहेगी। एजेंसी भारतीय मानसून का लो-प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत और पाकिस्तान से पश्चिम की ओर बढ़कर अरब प्रायद्वीप तक पहुंच रहा है, जिससे गर्म हवा का प्रवाह तेज हो गया है। अरब प्रायद्वीप पर बने थर्मल लो प्रेशर तापमान लगातार बढ़ा रहा है। रुब-अल-खाली रेगिस्तान से आने वाली अत्यधिक गर्म हवाएं तापमान को और ऊपर ले जा रही हैं। अरब की खाड़ी का समुद्री पानी इस समय काफी गर्म है, जिससे तटीय इलाकों में नमी बढ़ रही है।

ट्रंप के पोस्ट रीयल-टाइम में खरीद सकेंगे कारोबारी, सशुल्क डाटा सेवा शुरू

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया गतिविधियों का वित्तीय बाजारों पर बढ़ते प्रभाव के बीच ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने नई सशुल्क डाटा सेवा 'ट्रुथ एपीआई' शुरू की है। इसके जरिए कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को ट्रुथ सोशल पर प्रकाशित पोस्ट का रीयल-टाइम और लाइसेंस प्राप्त डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक अगस्त से 'ट्रुथ एपीआई' सेवा लॉन्च कर दी है। कंपनी का कहना है कि यह सेवा ग्राहकों को ट्रुथ सोशल पर प्रकाशित उन पोस्ट तक तेज और सीधी पहुंच देगी, जिनका वित्तीय बाजारों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिका के इडाहो में एक फास्ट-फूड रेस्तरां में गोलीबारी, हमलावर समेत 4 लोगों की मौत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के इडाहो राज्य के ट्विन फॉल्स शहर में एक 'इन-एन-आउट' रेस्तरां में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शनिवार दोपहर को एक बंदूकधारी ने रेस्तरां में अंधाधुंध गोलियां चला दीं। इस दर्दनाक हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। हमलावर ने बाद में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय पुलिस अधिकारियों और सीबीएस न्यूज ने रविवार को इस घटना की पुष्टि की।

पुलिस प्रमुख मैथ्यू हिक्स ने बताया कि हमलावर की पहचान 24 वर्षीय चैड विलियम्स के रूप में हुई है, जिसकी मौके पर ही खुद को गोली मारने से मौत हो गई। बता दें कि यह खौफनाक वारदात शनिवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:30 बजे हुई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग जान बचाने के लिए पार्किंग एरिया से भागते हुए नजर आए और गोलियों की आवाजें सुनाई दीं।

पुलिस प्रमुख ने बताया कि एक ऑ-ड्यूटी पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक ने तुरंत बहादुरी दिखाते हुए हमलावर का सामना किया और उससे गोलीबारी की। पुलिस का मानना है कि इन दोनों के साहसी कदम की वजह से हमलावर वहां से पीछे हटने पर मजबूर हुआ, जिससे और अधिक लोगों की जान बच गई।

सेंट ल्यूक मैजिक वैली मेडिकल सेंटर के अनुसार, 2 घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं, 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और 3 अन्य की स्थिति स्थिर है। इसके साथ ही 'इन-एन-आउट' की अध्यक्ष लिंसी स्नाइडर ने दुख जताते हुए पुष्टि की कि मृतकों में उनकी एक महिला कर्मचारी भी शामिल हैं, जो ग्राहकों की सेवा कर रही थीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावर के परिवार वाले जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हमले के पीछे असल वजह क्या थी।

होर्मुज के पास टैंकर के नजदीक धमाका

यूकेएमटीओ ने जारी किया अलर्ट; जहाज और चालक दल सुरक्षित

लंदन, एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास एक तेल टैंकर के नजदीक विस्फोट की आवाज सुनी गई। हालांकि, जहाज और उस पर सवार सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। यूकेएमटीओ की ओर से रविवार को जारी एडवाइजरी के अनुसार, एजेंसी को रविवार को ग्रीनविच समयानुसार रात 8:37 बजे जहाज के कप्तान से इसकी सूचना मिली। कप्तान ने बताया कि जब जहाज ओमान के खासाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में था, तभी उसके पास विस्फोट की आवाज सुनाई दी।

यूकेएमटीओ ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना एजेंसी को देने की सलाह दी है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बढ़े तनाव के बीच हाल के दिनों में यूकेएमटीओ ने समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई घटनाक्रम दर्ज किए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, इनमें से अधिकतर घटनाएं ओमान के तट और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास हुई हैं।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (वॉशिंगटन समयानुसार) कहा कि ईरान के साथ वार्ता सोमवार दोपहर से शुरू होगी। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कतर ने अमेरिका से प्रस्तावित सैन्य हमले रोकने का अनुरोध किया है, क्योंकि 'उन्हें लगता है कि समझौता हो सकता है।' जॉइंट बेस एंड्रयूज जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, 'होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर समझौता होगा।

द.कोरिया में पहली बार एआई अफसर ने संभाली नौसेना की कमान, समुद्र में बिना चालक जहाजों ने किया माइन ऑपरेशन

सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरिया की नौसेना ने समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नौसेना ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव रहित जहाजों की मदद से समुद्र में माइन (बारूदी सुरंग) खोजने और हटाने का सफल परीक्षण किया। यह संयुक्त अभ्यास दक्षिण कोरिया की रक्षा कंपनी हनव्हा सिस्टम्स के सहयोग से दक्षिण-पूर्वी शहर बुसान स्थित नौसैनिक अड्डे पर आयोजित किया गया। परीक्षण में 730 टन वजनी ओंगजिन माइंस्वीपर, जासूसी ड्रोन, दो मानव रहित सतही जहाज और एक स्वायत्त अंडरवाटर वाहन का इस्तेमाल किया गया। अभ्यास के दौरान यह काल्पनिक स्थिति बनाई गई कि दुश्मन ने बुसान बंदरगाह के समुद्री रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाकर उसे अवरुद्ध कर दिया है। इसके बाद एआई तकनीक की मदद से पूरे अभियान को संचालित किया गया। इस मिशन की सबसे खास बात एआई स्टाफ ऑफिसर सिस्टम रहा। इस एआई सिस्टम ने मौसम, समुद्री धाराओं और अन्य परिस्थितियों का विश्लेषण कर मानव कमांडर को रणनीतिक सुझाव दिए। एआई की रिपोर्ट के आधार पर मानव और मानव रहित जहाजों ने अलग-अलग क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों की तलाश की, जबकि जासूसी ड्रोन ने बंदरगाह के आसपास की गतिविधियों और वातावरण की निगरानी की। हालांकि परीक्षण में इस्तेमाल किए गए मानव रहित जहाज अभी माइन हटाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन दक्षिण कोरियाई नौसेना का कहना है कि भविष्य में इन्हें इस क्षमता से लैस किया जाएगा। नौसेना के अनुसार, इस परीक्षण ने साबित किया कि एआई आधारित निर्णय प्रणाली, मानव चालक दल और मानव रहित जहाजों का संयुक्त संचालन भविष्य के समुद्री युद्ध अभियानों को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना सकता है।

पाकिस्तान को नहीं पचा पीओके का सच, विरोध प्रदर्शन की खबरें कवर करने वाली कई वेबसाइट्स पर लगाई रोक

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चल रही अशांति की बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज के बाद पाकिस्तान ने कई न्यूज वेबसाइट्स रोक लगा दी है और डिजिटल सेंसरशिप बढ़ा दी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय और क्षेत्रीय न्यूज वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की खबरों के साथ-साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में यूजर्स के लिए इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स तक पहुंच भी बंद हो गई है।

किन वेबसाइट्स पर लगाई गई पाबंदियां: ये पाबंदियां उन प्लेटफॉर्म्स पर लगाई गई हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हालिया विरोध-प्रदर्शनों, कथित सुरक्षा कार्रवाई और लोगों में बढ़ते असंतोष को कवर कर रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन पाबंदियों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। 24 जून के अदालती आदेश के अनुसार, जिन चैनलों को ब्लॉक किया जा सकता है उनमें

पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े चैनल, साथ ही सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकार शामिल हैं। कई यूट्यूब चैनल भी हुए ब्लॉक इससे पहले जुलाई में अल जजीरा ने रिपोर्ट दी थी कि इस्लामाबाद की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 2 जून की रिपोर्ट के आधार पर कई यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित प्रतिबंधों से पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी और सीमित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीविजन और प्रिंट मीडिया पर भारी पाबंदियों के बीच सोशल मीडिया ही सार्वजनिक बहस और असहमति जाहिर करने के कुछ बचे हुए मंचों में से एक है। उनके चैनल ब्लॉक किए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध पीओके में राजनीतिक हालात और स्थानीय विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी जानकारी के प्रसार को लेकर बढ़ी हुई संवेदनशीलता के बीच लगाए गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में चुनाव के दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर व्यवधान, लॉजिस्टिकल चुनौतियां और लगातार विरोध-प्रदर्शन देखने को मिले, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर नए सिरे से चिंताएं पैदा हो गई हैं।

यूरोप में गैंग सोशल मीडिया से टीनएजर्स को बना रहे हैं भाड़े के कातिल, एजेंट 47 के इशारे पर हो रहीं थी हत्याएं

लंदन , एजेंसी। यूरोप में अब क्राइम गैंग सोशल मीडिया के जरिए टीनएजर्स को रिक्रूट करके उनसे पैसे के बदले मर्डर करवा रहे हैं। यह चेतावनी यूरोपोल ने दी है। पुलिस इसे वायलेंस-एज-ए-सर्विस यानी हिंसा को सेवा के रूप में

बेचना बता रही है।

इस रैकेट के पीछे मुख्य नाम स्वीडन का फॉक्सट्रॉट नेटवर्क है। पुलिस का मानना है कि ये गैंग 2022 से अब तक करीब 35 मर्डर के लिए जिम्मेदार है। गैंग पर यूरोप में इजरायली टारगेट पर हमले और ईरान सरकार से लिंक होने का भी आरोप है।

रावा मजीद करता है लीड: इस गैंग को रावा मजीद लीड करता है, जो स्वीडन से भागकर पहले तुर्की और अब तेहरान, ईरान में रह रहा है। च सरकार ने 2025 में मजीद और फॉक्सट्रॉट पर बैन लगाया था। इस तरह से फंसाते हैं टीनएजर्स को यह गैंग युवाओं को सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं। उन्हें मोटे कैश का लालच देकर भाड़े का कातिल बनाते हैं। कई बार पेमेंट मिलती ही नहीं क्योंकि उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। इस साल 2 बड़े मामले सामने आए हैं।

अटिला अजीमोव (18) ने पिछले साल फरवरी में इसने स्टॉकहोम में एक 20 साल के स्टूडेंट को गोली मार दी थी। अजीमोव ने पैसे के लिए ये काम किया था, लेकिन पेमेंट से पहले ही पकड़ा गया। उसे उम्रकैद हुई।

जोहान्स नैटलैंड ने इसे च में वेस्ट यॉर्कशायर में एक मर्डर की साजिश के लिए सजा हुई। नैटलैंड को पहला मैसेज मिला था इंग्लैंड में किलिंग 270के यानी 270,000 नॉर्वेजियन क्रोनर।

जोहान्स को जेनरेलेन नाम के 16 साल करे लड़के ने हायर किया, जो खुद एक चिल्ड्रन होम में रहता था। फिर एजेंट 47 यानी पॉपुलर वीडियो गेम के नाम से एक मेंबर ने उसकी मैनचेस्टर की वन-वे फ्लाइट और इमरजेंसी पासपोर्ट का इंतजाम किया।

नैटलैंड को सिग्नल ऐप पर इंस्ट्रक्शन मिले। उसे मैप और वीडियो भेजे गए जिसमें बताया गया कि हडर्सफील्ड के पास जंगल में बंदूकें कहां हैं और कैश कहां छिपा है। हमले से पहले ही ब्रिटिश पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि जेनरेलेन ने अजीमोव और दक्षिणी स्वीडन में एक और 17 साल के लड़के को भी रिक्रूट किया था। यूरोपोल के यूरोपियन सीरियस एंड ऑर्डनाइज्ड क्राइम सेंटर के हेड एंडी क्रैग ने इसे कमजोर युवाओं की सोची-समझी हत्या की आउटसोर्सिंग कहा। इसके जवाब में यूरोपोल ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें 11 यूरोपीय देशों की पुलिस है। पिछले 15 महीनों में 280 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार लोगों में अली शहाद अहमद भी है, जिसे एजेंट 47 माना जाता है। से इराक से पकड़ा गया है और स्वीडन ने उसके एक्सट्रेडिशन की मांग की है।

2015 से ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ी रफ्तार, शोधकर्ताओं ने किया खुलासा

वॉशिंगटन, एजेंसी। विज्ञानियों ने पता लगाया है कि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार बढ़ गई है। 2015 के आसपास से ग्लोबल वार्मिंग की रफ़्तार बढ़ी है। पाट्सडैम इंस्टीट्यूट फार क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च (पीआइके) के विश्लेषण के आधार पर विज्ञानियों ने यह दावा किया है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया का तापमान लगभग 0.35ए डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की अनुमानित रफ़्तार से बढ़ रहा है। 1970 से 2015 के बीच तापमान बढ़ने की औसत दर 0.2एडिग्री सेल्सियस प्रति दशक से थोड़ी कम थी। यह अध्ययन वैज्ञानिक जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है।

साइंस डेली की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सांख्यिकी विशेषज्ञ और इस अध्ययन के सह-लेखक ग्रांट फोस्टर ने कहा, हम 2015 के आसपास से ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आई है।

तापमान के सभी पांचों रिकार्ड में एक जैसा ही पैटर्न दिखा, भले ही ये डाटा अलग-अलग वैज्ञानिक संगठनों ने तैयार किए थे और इनमें अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। सभी डेटासेट में ग्लोबल वार्मिंग में 2013 या 2014 में दिखने लगी थी। शोधकर्ता इस

भारत-तालिबान की नजदीकियों से परेशान हुआ नापाक पड़ोसी पाकिस्तान, बौखलाहट में अफगान शासन को बताया गुलाम

इस्लामाबाद, एजेंसी। दुनियाभर में कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान की गीदड़भभकी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में एक बार फिर अब नापाक पड़ोसी पाकिस्तान की झुंझलाहट और भारत-अफगानिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों से बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। इसी क्रम में नापाक पड़ोसी की खराब मंशा तब सामने आई, जब पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत और तालिबान के संबंधों पर जहर उगला। इतना ही नहीं भारत-अफगानिस्तान के रिश्ते को मालिक और गुलाम बताया और अफगान तालिबान पर जमकर भड़ास निकाली।

'लिविंग नास्त्रेदमस' का दावा: 2026 की दो भविष्यवाणियां सच, अब आने वाला है तीसरा बड़ा संकट...

ब्रासीलिया , एजेंसी। ब्राज़ील के 39 वर्षीय रहस्यवादी एथोस सैलोम, जिन्हें लिविंग नास्त्रेदमस कहा जाता है। उनका दावा है कि 2026 के लिए उनके द्वारा की गई उनकी दो बड़ी भविष्यवाणियां पहले ही सच साबित हो चुकी हैं। अब वह दुनिया को तीसरी घटना के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सैलोम पहले कोविड-19 महामारी और महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय की मृत्यु जैसी घटनाओं की कथित भविष्यवाणी को लेकर चर्चा में आए थे। हाल ही में उन्होंने अपनी 2026 की भविष्यवाणियों की समीक्षा करते हुए कहा कि उनकी दो बड़ी बातें सच हो गई हैं।

उनके अनुसार, पहली भविष्यवाणी मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर थी। उन्होंने दावा किया था कि इज़राइल और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद और सैन्य तनाव बढ़ सकता है।

सैलोम का दूसरा दावा 2026 फीफा विश्व कप को लेकर था। उनका कहना है कि उन्होंने स्पेन की जीत का संकेत पहले ही दे दिया था। उन्होंने अपने पुराने विज़न का हवाला देते हुए कहा था कि विजेता टीम आग के रंग से जुड़ी होगी। हालांकि

आलोचकों का कहना है कि उन्होंने शुरू में कई संभावित देशों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन खुद को भविष्य बताने वाले इस व्यक्ति का कहना है कि स्पेन ही उनकी पहली पसंद थी।

वहीं, उन्होंने कहा, जब दुनिया भर के कई साइकिक और कमेंटेटर पुर्तगाल या दूसरे देशों के ट्रॉफी उठाने की भविष्यवाणी कर रहे थे, मैंने फाइनलिस्ट की पहचान की और बार-बार स्पेन को सबसे संभावित चैंपियन बताया। नतीजे में अब वे भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। अपनी अगली चेतावनी में सैलोम ने आर्कटिक क्षेत्र को लेकर रूस और नाटो के बीच संभावित टकराव की बात कही है। उनका दावा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलती बर्फ नए समुद्री मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान बना रही है, उन्होंने चेतावनी दी है कि तेजी से पिघलती ध्रुवीय बर्फ कीमती एनर्जी रिज़र्व और ज़रूरी शिपिंग रूट को उजागर कर रही है, जिससे जमी हुई उत्तरी सीमा एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल लड़ाई का मैदान बन रही है। इस इलाके में मिलिट्री तैनाती बढ़ने के साथ, सैलोम को डर है कि स्थिति सीधे ग्लोबल लड़ाई में बदल सकती है।

मिस्र में भूकंप के तेज झटके: शर्म अल-शेख के पास आया 5.5 तीव्रता का भूकंप

काहिरा, एजेंसी। मिस्र में सोमवार सुबह शर्म अल-शेख के उत्तर-पूर्वी इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। देश के राष्ट्रीय खगोलीय और भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने यह जानकारी दी। संस्थान के अनुसार, भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 3 बजे (0000 जीएमटी) आया। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप का केंद्र 30.19 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 32.61 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। संस्थान ने बताया कि उसे लोगों से जानकारी मिली है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन किसी की जान जाने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के संवाददाताओं ने भी मिस्र की राजधानी काहिरा में भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के बाद मिस्र के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री खालिद अब्देल-गफ्फार ने देश की स्वास्थ्य आपातकालीन योजना को तुरंत लागू करने और मंत्रालय के केंद्रीय संकट एवं आपातकालीन संचालन कक्ष की बैठक बुलाने का आदेश दिया। मंत्रालय ने देशभर के अस्पतालों में आपातकालीन और गंभीर मरीजों के इलाज वाले विभागों में अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया है। साथ ही एंबुलेंस और तुरंत कार्रवाई करने वाली टीमों को तैयार रहने को कहा है। मंत्रालय ने कहा, स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बनी हुई है और भूकंप से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मिस्र के रेड क्रिसेंट ने भी उन शहरों में आपात तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। संगठन ने बताया कि उसे किसी की मौत या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली है। मिस्र स्वेज की खाड़ी, लाल सागर और अकाबा की खाड़ी के आसपास सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्रों के पास स्थित है।

स्प्रेयर मशीन वितरण में पक्षपात का आरोप, कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, पात्र किसानों को लाभ नहीं मिलने की शिकायत..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

खरीफ सीजन में धान की बुआई अंतिम चरण में है और किसानों को फसलों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए स्प्रेयर मशीन की जरूरत है। इसी बीच बरमकेला कृषि विभाग द्वारा स्प्रेयर मशीन वितरण में पक्षपात के आरोप सामने आए हैं। मंगलवार को बरमकेला विकासखंड के किसान कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे और डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) मद से स्प्रेयर मशीन उपलब्ध कराने के साथ वितरण प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की।

पात्र होने के बावजूद नहीं मिला लाभ

मंगलवार दोपहर करीब 12:40 बजे ग्राम पंचायत बिलाईगढ़-अ के किसान अनिल कुमार साहू, संजय पटेल और सत्येंद्र पटेल ने कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू से मुलाकात कर अपनी शिकायत रखी। किसानों ने बताया कि सोमवार को कृषि विभाग बरमकेला परिसर में स्प्रेयर मशीनों का वितरण किया गया, लेकिन पात्र होने के बावजूद उनका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया गया। जबकि उनके गांव के अन्य किसानों को मशीनें वितरित कर दी गई।

किसानों ने मांग की कि डीएमएफ मद से जरूरतमंद और छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर स्प्रेयर मशीन उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

किसानों का आरोप है कि स्प्रेयर मशीन वितरण के लिए सरपंच और जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर सूची तैयार की जाती है। इससे वास्तविक जरूरतमंद किसानों की जगह प्रभावशाली और चहेते लोगों को लाभ मिल जाता है। उनका कहना है कि यदि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती, तो उन्हें अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट नहीं आना पड़ता। किसानों ने बताया कि धान की फसल में समय पर कीटनाशक का छिड़काव करना बेहद जरूरी होता है। स्प्रेयर मशीन नहीं मिलने से खेती का काम प्रभावित हो रहा है। मशीन की कीमत अधिक होने के कारण छोटे और सीमांत किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में शासन की योजना के तहत मिलने वाली स्प्रेयर मशीन उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।

निष्पक्ष जांच और पात्र किसानों को लाभ देने की मांग

किसान अनिल कुमार साहू ने कहा कि योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।किसानों का कहना है कि यदि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तो सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ उन किसानों तक पहुंचेगा, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

कचरे के शेड में भविष्य गढने को मजबूर देश के नवनिहाल

जर्जर स्कूल पर प्रशासन बेखबर, एक कमरे में ठूंसे गए 32 बच्चे, मिड-डे मील के लिए आधा किलोमीटर चलते हैं पैदल

रायगढ़/मूक पत्रिका

विकासखंड लैलूंगा के ग्राम पंचायत आमपाली के आश्रित ग्राम राजाआमा स्थित प्राथमिक शाला की बदहाल व्यवस्था ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां पहली से पांचवीं कक्षा तक के कुल 32 छात्र-छात्राएं एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन अत्यधिक जर्जर होने के कारण बच्चों की कक्षाएं पृथक्करण (शेड) में संचालित की जा रही हैं, जिसे ग्रामीण 'कचरा शेड' जैसी स्थिति वाला बता रहे हैं।सबसे चिंताजनक बात यह है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) करने के लिए करीब आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चों को प्रतिदिन इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही हैं। विद्यालय के सहायक शिक्षक बुद्धदेव बेहरा ने बताया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उनका कहना है कि बच्चों को जर्जर भवन के कारण शेड में बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है और भोजन के लिए दूर ले जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की गई थी। अधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण भी किया, लेकिन आज तक न तो नया भवन बना और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से तत्काल नए स्कूल भवन के निर्माण तथा बच्चों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब अधिकारी स्वयं स्थिति देखकर लौट चुके हैं, तो आखिर कार्रवाई कब होगी? क्या किसी हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी, या फिर राजाआमा के मासूमों को जल्द सुरक्षित स्कूल की सौगात मिलेगी?

उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे पांच मवेशी मुक्त, एक आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर/मूक पत्रिका

दुर्गेश गुप्ता । बसंतपुर थाना पुलिस ने पशुओं की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे पांच मवेशियों को मुक्त कराया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 4 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पांच भैंसों को क्रूरतापूर्वक हांकते हुए उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम उमेश कुमार यादव (32 वर्ष), निवासी ग्राम कुंदी, थाना बसंतपुर बताया।आरोपी के कब्जे से पांच भैंसें बरामद कर सुरक्षित जब्त की गई। पुलिस ने उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 128/2026 दर्ज करते हुए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण निवारण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत कार्रवाई की।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति के कहने पर मवेशियों को ले जा रहा था और इसके बदले उसे ?2,500 मिलने थे। पुलिस अन्य आरोपियों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

सीएम हेल्पलाइन बनी शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान का सशक्त माध्यम

शिक्षा विभाग ने 96 शिकायतों का किया समयबद्ध निराकरण, नागरिकों ने राज्य सरकार के प्रति जताया आभार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

राज्य सरकार द्वारा संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर सामने आई है। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे लोगों का शासन-प्रशासन पर विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा भी नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करते हुए उन्हें त्वरित राहत प्रदान की जा रही है। जिला बेमेतरा के शिक्षा विभाग को अब तक 116 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था, शिक्षक की मांग, स्कूलों में प्रवेश,

छात्रवृत्ति, गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, आधारभूत अधोसंरचना, मध्यान्ह भोजन तथा विद्यालयों के उन्नयन जैसी विभिन्न समस्याएं शामिल थीं। विभाग द्वारा इन शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए 96 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है।निराकृत शिकायतों में से 63 मामलों में नागरिकों ने सकारात्मक फीडबैक देते हुए समाधान पर संतोष व्यक्त किया है, जबकि शेष शिकायतों में फीडबैक की प्रक्रिया जारी है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि शिक्षा विभाग नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य कर रहा है। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लाभान्वित नागरिकों ने कहा कि उनकी शिकायतों का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान होने से उन्हें अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जनहितैषी पहल की सराहना करते हुए शासन एवं प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उनका कहना है कि सीएम हेल्पलाइन आमजन और शासन के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बन गई है, जहां प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और समयबद्ध ढंग से उसका निराकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सरल, पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराना है। इसी सोच के साथ संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा शिकायतों की नियमित समीक्षा कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे सुशासन की अवधारणा धरातल पर साकार हो रही है।

यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, 5 पिकअप वाहनों पर 25 हजार का जुर्माना, नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों पर भी कार्रवाई..

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। अभियान के तहत बिना परमिट वाहन संचालन, ओवरलोडिंग और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यातायात सेल की सघन जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 5 पिकअप वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों को भविष्य में नियमों का पालन करने की भी समझाइश दी।

नाबालिग वाहन चालकों पर भी कार्रवाई-अभियान के दौरान वाहन चलाते मिले 2 नाबालिग स्कूली बच्चों के मामलों में उनके अभिभावकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 4/181 और 5/180 के तहत कार्रवाई करते हुए 4 हजार रुपये का चालान किया गया। पुलिस ने अभिभावकों को स्पष्ट रूप से समझाया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने देना कानूनन अपराध है। पुलिस के अनुसार जिले में लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले की तुलना में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में कमी आई है। वहीं अब कई अभिभावक स्वयं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जा रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है।

पुलिस की अपील-यातायात सेल ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन न चलाने दें।

पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है और नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

दो साल बाद भी शुरू नहीं हुआ जर्जर स्कूलों का निर्माण, जनपद सदस्य ने कलेक्टर को लिखा पत्र..

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

बरमकेला विकासखंड के कई शासकीय स्कूलों के नए भवन और मरम्मत कार्य की स्वीकृति मिलने के दो वर्ष बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर जनपद सदस्य नीलम किशोर पटेल ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की है।पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2023 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कई जर्जर स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत की स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए जुलाई 2023 में टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

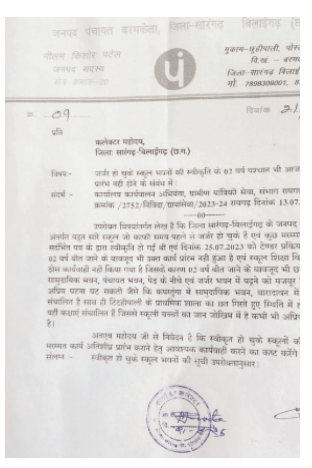

खुले स्थानों और जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर बच्चे-पत्र में उल्लेख किया गया है कि भवन नहीं बनने के कारण कई स्कूलों के छात्र-छात्राएं आज भी चौपाल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और पेड़ों के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वहीं कई जगह जर्जर भवनों में ही कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। पत्र में कपरतुंगा, बारादावन और टिटहीपाली जैसे स्कूलों का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कहीं स्कूल सामुदायिक भवन में तो कहीं पंचायत भवन में संचालित हो रहे हैं। वहीं टिटहीपाली प्राथमिक शाला की छत जर्जर होने के बावजूद वहीं बच्चों की पढ़ाई जारी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

जल्द निर्माण शुरू कराने की मांग-जनपद सदस्य नीलम किशोर पटेल ने कलेक्टर से पत्र के माध्यम से मांग की है कि जिन स्कूलों के भवन निर्माण और मरम्मत कार्य की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, उनका काम तत्काल शुरू कराया जाए। उनका कहना है कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मिलना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इस मामले में अब और देरी नहीं होनी चाहिए।उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

29 लाख के नए फंड पर सरपंच की 'गिद्ध नजर': SDM कोर्ट में धारा 40 के बावजूद बड़े खर्री में सरकारी खजाने की खुली डकैती की तैयारी!

सारंगढ़/बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत बड़े खर्री (खर्री बड़े) में स्थानीय लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जिस सरपंच पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत अनुविभागीय अधिकारी (स्छरू) कोर्ट में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 का बेदखली प्रकरण विचाराधीन है, वही सरपंच अब 29 लाख रुपये से अधिक के नए सरकारी फंड को ठिकाने लगाने की फिराक में है!दस्तावेजी सबूतों के साथ का यह सबसे बड़ा खुलासा है कि कैसे कानूनी शिकंजे में घिरे होने के बावजूद सरपंच की नजरें गांव के विकास के नाम पर आए लाखों रुपयों पर टिकी हैं।

29.24 लाख रुपये का नया वर्क ऑर्डर और गबन की सीधी आशंका

ग्राम पंचायत बड़े खर्री के उपसरपंच, पंचों और सजग ग्रामीणों ने प्रशासनिक तंत्र पर सीधा हमला बोलते हुए आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। गौण खनिज रॉयल्टी मद से 08 कार्य स्वीकृतः जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा 27 जनवरी 2026 को गौण खनिज रॉयल्टी मद के तहत 29,24,500 रुपये (उनतीस लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) के 08 निर्माण कार्यों का कार्यादेश जारी किया गया है।14 अगस्त 2026 को अगली सुनवाईः स्छरूकोर्ट में सरपंच गिरिजा प्रसाद पटेल के खिलाफ धारा 40 का मामला अंतिम दौर में है, जिसकी अगली सुनवाई 14 अगस्त 2026 को तय है। खजाने पर डाका डालने की तैयारीः उपसरपंच और पंचों को गंभीर आशंका है कि फैसला आने से पहले ही सरपंच और सचिव की मिलीभगत से इस 29.24 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि का बैंक खातों से आहरण कर बंदरबांट कर लिया जाएगा।

29 जनवरी से सो रहा था प्रशासन, 5 अगस्त को फिर ग्रामीणों ने घेरा

यह कोई पहला मौका नहीं है जब ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। 29 जनवरी 2026: ग्रामीणों ने सबसे पहले आवेदन देकर खातों के आहरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। 05 अगस्त 2026: महीनों बीत जाने के बाद भी जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो 5 अगस्त 2026 को उपसरपंच और पंचगणों (जिसमें श्रीमती कृष्णा यादव मालती सिदार, विमला पटेल, सिल्या बाई, ज्योतिप्रभा पटेल, रेशम लाल पटेल, रूपसिंह, नरगीबाई आदि शामिल हैं) ने पुनः लिखित आवेदन सौंपकर खाता तत्काल होल्ड करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यदि शासकीय धनराशि का दुरुपयोग होता है, तो इसके लिए संबंधित पंचायत प्रतिनिधि और मौन प्रशासनिक अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।सब कुछ जानते हुए भी मौन धारण किए बैठे हैं ष्टश्वह्र राधेश्याम नायक!मामले का सबसे निराशाजनक पहलू प्रशासनिक संरक्षण का है। जनपद पंचायत सारंगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ष्टश्वह्र) राधेश्याम नायक की भूमिका अब पूरी तरह सवालों के घेरे में है।जब स्छरू कोर्ट में धारा 40 का मामला लंबित है और ग्रामीणों ने जनवरी से लेकर अगस्त तक बार-बार लिखित शिकायतें दी हैं, तब भी खाते फ्रीज करने के बजाय वर्क ऑर्डर जारी कर आहरण की खुली छूट क्यों दी गई? ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, तो ष्टश्वह्र राधेश्याम नायक ने कोई सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के स्थान पर मामले को ÷आपस में बैठकर ले-देकर सलटाने÷ जैसी गैर-जिम्मेदाराना सलाह दे डाली।उल्टा शिकायतों से ÷विकास कार्य प्रभावित होने÷ का रोना रोकर भ्रष्टाचारियों को बचाते नजर आए।29.24 लाख रुपये के इस खेल में आखिर किसकी शह मिली हुई है? क्या सारंगढ़ जनपद ष्टश्वह्र राधेश्याम नायक कानून के नियमों का पालन करवाएंगे और 14 अगस्त की सुनवाई तक खाता होल्ड करेंगे, या फिर शासकीय धन की इस संभावित डकैती के मूकदर्शक बने रहेंगे?

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता परखी, मरीजों एवं बच्चों से की आत्मीय बातचीत, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने बुधवार को जिला चिकित्सालय बेमेतरा का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई, मरीजों को मिल रही सुविधाओं एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया तथा अस्पताल के प्रशासनिक कार्यों एवं अभिलेखों की जानकारी प्राप्त की।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने मरीजों से उपचार, चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता, जांच सुविधाओं तथा अस्पताल में मिलने वाली अन्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल में उपचार हेतु आए बच्चों से भी उन्होंने आत्मीयता से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं।कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षालय तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने सिविल सर्जन एवं संबंधित अधिकारियों से अस्पताल की व्यवस्थाओं, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति, आवश्यक दवाओं के भंडारण, चिकित्सा उपकरणों की कार्यशील स्थिति तथा मरीजों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही अस्पताल में स्वच्छ एवं सकारात्मक वातावरण बनाए रखने तथा मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं सेवा भावना के साथ करें, ताकि जिले के नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सहित अस्पताल के चिकित्सक, संबंधित अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।

बेमेतरा में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल!, बच्चों की भविष्य पर संकट

शिक्षकों की कमी से जूझ रहा आत्मानंद स्कूल, पालकों ने बेमेतरा कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से लगाई गुहार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, शिवलाल राठी, बेमेतरा में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर पालकों का आक्रोश सामने आया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से चिंतित पालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। पालकों का कहना है कि विद्यालय में कई विषयों के शिक्षक नहीं होने के कारण नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और भविष्य पर पड़ रहा है। अभिभावकों ने सवाल उठाया कि जब विद्यालय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मॉडल बनाया गया है, तो फिर शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे संवर पाएगा?ज्ञापन में मांग की गई है कि विद्यालय के सभी रिक्त शिक्षकीय पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।बताया गया कि यह ज्ञापन 3 अगस्त 2026 को जिला जनदर्शन के माध्यम से कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है। इससे एक सप्ताह पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर शिक्षा की कमी को दूर करने वालों को नहीं गुहार लगाई थी किंतु किसी प्रकार प्रतिक्रिया नहीं होने पर जिला कलेक्टर बेमेतरा को ज्ञापन देकर शिक्षक की मांग की है।

पालकों का सवाल

÷जब स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया गया है, तो बिना शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी?÷, अब सबकी नजर प्रशासन परशिक्षकों की कमी का यह मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। अभिभावकों और विद्यार्थियों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या पर त्वरित निर्णय लेकर रिक्त पदों को भरेगा। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा परिणाम पर गंभीर असर पड़ सकता है।

केशकाल में सर्व आदिवासी समाज ने तीन प्रमुख चौराहों के नामकरण की उठाई मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

केशकाल/मूक पत्रिका

नगर पंचायत केशकाल क्षेत्र के तीन प्रमुख सार्वजनिक चौराहों को आदिवासी महापुरुषों के नाम से आरक्षित एवं व्यवस्थित करने की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज, केशकाल ब्लॉक इकाई ने सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज ने बताया कि केशकाल आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहां के सार्वजनिक स्थलों का नामकरण आदिवासी समाज के महानायकों के नाम पर किया जाना चाहिए। इससे क्षेत्र के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास, पूर्वजों के त्याग, संघर्ष और सामाजिक योगदान से प्रेरणा मिलेगी।समाज ने नगर पंचायत क्षेत्र के तीन प्रमुख चौराहों के लिए निम्न प्रस्ताव रखे हैं–भूमियार केशो मुरिया चौक - वीर योद्धा एवं समाज सुधारक भूमियार केशो मुरिया के नाम पर।भगवान बिरसा मुंडा चौक - आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर।गुंडाधूर चौक - वर्ष 1910 के आदिवासी विद्रोह के महानायक गुंडा धूर के नाम पर।सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि इन तीनों स्थानों पर नाम पट्टिका स्थापित की जाए, उनका सौंदर्यीकरण एवं समुचित विकास कराया जाए तथा शासकीय अभिलेखों में भी इन नामों को दर्ज किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो समाज व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज, केशकाल ब्लॉक के अध्यक्ष, सचिव सहित बड़ी संख्या में समाज के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वेतन रुकने से स्वास्थ्य कर्मियों पर आर्थिक संकट, जनपद सदस्य दीपक सिंह दिनकर ने CMHO को सौंपा ज्ञापन, 7 दिन में भुगतान न होने पर घेराव की चेतावनी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जनपद सदस्य दीपक सिंह दिनकर ने जिले के समस्त स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन अभिलंब भुगतान करने की मांग को लेकर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब हो कि बीते 21 जुलाई 2026 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जिला कोषालय अधिकारी को वेतन आहरण रोकने के संबंध में आदेश जारी किया गया था।जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लक्ष्य के प्रति उपलब्धियां निराशाजनक होने का जिक्र करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा माह जुलाई 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोकना निर्देश की बात कही गई है। आदेश के परिपालन में बेमेतरा जिला के स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी (नियमित/ संविदा) का माह जुलाई से आगामी आदेश तक वेतन आहरण रोक दिया गया है। वेतन रुकने से इनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। घर का पालन-पोषण, बच्चों की शिक्षा और बैंक की किस्तों श्वस्ढ्ढ के भुगतान का संकट खड़ा हो गया है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय साख ष्टढ्ढक्चढ्ढरु भी प्रभावित हो रही है। उन्हें मानसिक तनाव के साथ-साथ रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी परेशानी हो रही है।जनपद सदस्य दीपक सिंह दिनकर ने कहा कि जिले में अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के सामने आज वेतन संकट खड़ा हो गया है। अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों की प्रगति में कोई दिक्कत आई है तो जिम्मेदार अधिकारियों की पर कार्रवाई की जाए ना कि पूरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का वेतन रोका जाए। उन्होंने 7 दिवस के भीतर बकाया वेतन का भुगतान कराने मांग किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में समाधान नहीं हुआ तो विवश होकर स्वास्थ्य अमले को शांतिपूर्ण घेराव का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अमृतलाल रोहडेकल ने आश्वासन देते हुए समस्त अधिकारी कर्मचारियों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यक्रम में प्रगति रिपोर्ट लक्ष्य केंद्र रूप बढ़ाने अपील की है।

सिंघौरी के स्कूली बच्चों ने सैनिकों को भेजीं राखियां, शुभकामना पत्र और गांव की पावन मिट्टी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघौरी के विद्यार्थियों ने देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के प्रति सम्मान और स्नेह का अनूठा संदेश दिया। विद्यार्थियों ने अपने हाथों से सुंदर रक्षा सूत्र (राखियां) तैयार कर सैनिकों के लिए शुभकामना पत्र लिखे तथा गांव की पावन मिट्टी भी उनके नाम प्रेषित की।बच्चों ने गांव की मिट्टी को मातृभूमि का चंदन बताते हुए संदेश दिया कि गांव की खुशबू, अपनों का स्नेह और देशवासियों का आशीर्वाद हमेशा देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के साथ है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए संदेशों में जवानों के स्वस्थ, सुरक्षित और गौरवपूर्ण जीवन की कामना की गई।संस्था प्रमुख सरस्वती साहू ने कहा कि देश के वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात सीमाओं की रक्षा करते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर उनके प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।शिक्षकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। बच्चों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ राखियां तैयार कर गांव की पावन मिट्टी को चंदन स्वरूप पैक किया और सैनिक भाइयों के लिए भेजा। इस प्रेरणादायी पहल की अभिभावकों एवं ग्रामीणों ने भी सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक संवेदनशीलता और देश के प्रति समर्पण की भावना को और अधिक सशक्त बनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रमुख सरस्वती साहू के मार्गदर्शन में देवेंद्र साहू, नुतेश्वर चंद्राकर, प्रशांत बघेल, शशिकला यादव, किरण खरे, संकुल समन्वयक धनीराम बंजारे, पूनम साहू, साजन वर्मा एवं विनीता श्रीवास सहित विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।

आंगनबाड़ी केंद्र बना नन्हें कदमों की पहली पाठशाला: स्वागत चार्ट से बढ़ रहा आत्मविश्वास, गीत-खेलों से सीख रहे बच्चे, पौष्टिक आहार से संवर रहा भविष्य

बलरामपुर/मूक पत्रिका

दुर्गेश गुप्ता – बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव उनके शुरुआती वर्षों में रखी जाती है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्र अब केवल पोषण वितरण तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि प्रारंभिक शिक्षा, खेलकूद और सर्वांगीण विकास के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में आकर्षक स्वागत चार्ट, रंग-बिरंगे शिक्षण सामग्री, गीत-संगीत, खेल-खेल में सीखने की गतिविधियां और बाल-अनुकूल वातावरण बच्चों को विद्यालय के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे सहज रूप से सीखने की प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। केंद्रों में बच्चों को आयु के अनुरूप पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को मजबूती मिल रही है। नियमित स्वास्थ्य निगरानी और पोषण पर विशेष ध्यान देकर कुपोषण को कम करने की दिशा में भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल से आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप लगातार बदल रहा है। अब ये केंद्र बच्चों के लिए ऐसी पहली पाठशाला बन रहे हैं, जहां शिक्षा, संस्कार, पोषण और खेल का समन्वय देखने को मिलता है। अभिभावक भी अपने बच्चों में आ रहे सकारात्मक बदलाव से संतुष्ट हैं।इन प्रयासों से स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी केंद्र नन्हे बच्चों के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं और प्रारंभिक शिक्षा को नई दिशा दे रहे हैं।

वर्तमान संगठित जिला साहू संघ के द्वारा मतभिन्नता के कारण नया संगठन का पंजीयन -संरक्षक शत्रुहन साहू

अधिकार क्षेत्र से बाहर लिया गया निर्णय

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बेमेतरा साहू संघ द्वारा विगत दिनों बैठक कर सामानांतर संगठन से जुड़े सामाजिक संस्था कह कर समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों का प्राथमिक एवं आजीवन सदस्यता समाप्त कर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बाहर का रास्ता दिखाने का अधिकार नही है। यह जानकारी देते हुए नव गठित जिला साहु संघ के संरक्षक शत्रुघ्न साहु ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया इस संबंध में उन्होंने बताया है कि यह अधिकार केवल और केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ रायपुर को है। यह निर्णय लेकर समाज के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वर्तमान जिला साहू संघ का निर्वाचन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर व उद्योग सचिव रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी महानदी भवन नया रायपुर मे सुनवाई हेतु प्रकरण लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय के नियमों के अवमानना कर छ.ग. प्रदेश साहू संघ व जिला साहू संघ के पदाधिकारियों द्वारा समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जबकि नवगठित जिला साहू संघ का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी दुर्ग संभाग दुर्ग से हुआ है। जिसका पंजीयन क्र. 122202651838 विधिवत पंजीकृत संस्था है। जबकि वह संस्था छ.ग. प्रदेश साहू संघ के द्वारा संचालित संस्था है। इसलिए इस संस्था को निष्कासित करने का अधिकार नही है।जिला साहू संघ के संरक्षक ने कहा कि संघ का उद्देश्य पारदर्शी सशक्त एवं शुध्द समाज का गठन कर रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक संगठन को आगे बढ़ाना है। लेकिन छ.ग. प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बेमेतरा जिला को महत्व नही दिया गया और किसी भी बातों को बार-बार आवेदन व निवेदन करने के बाद भी नही सुना गया। न ही हमारे बातों व पक्षों को सुनने का कोई भी मौका नही दिया गया। समाज के पीड़ित पक्ष आवेदन देकर भी उनके पक्ष में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया तथा अपने ही द्वारा निकाले गये निर्वाचन के संबंध मे दिशा व निर्देश मे सन 2024 तक जो भी सदस्य या व्यक्ति आजीवन सदस्य बने है उनको ही मतदान करने का अधिकार होगा। करके पत्र जारी किया गया था लेकिन अपने ही नियमों को बार बार बदलना तथा नियम का खुद पालन नही करना जिससे समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। जबकि पूरे छ.ग. साहू समाज मे सन् 2024 तक के आजीवन को ही मतदान की पात्रता दिया गया है लेकिन सिर्फ बेमेतरा जिला साहू संघ के लिए सन 2025 मे 1264 आजीवन सदस्य बना है उनको शामिल कराकर निर्वाचन कराया गया जिसका समाज द्वारा विरोध भी किया गया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तानाशाह रवैये के चलते शांतिप्रिय जिला साहू संघ बेमेतरा मे पूरा विवाद की स्थिति बन गई है। समाज को विघटित करने मे समाज के तथाकथित कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए विवाद की स्थिति पैदा किया गया। जिसके कारण आज नया जिला साहू समाज का पंजीयन करवाना पड़ा। जिसमे लगभग 450 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण किया गया है। जिसे दबावपूर्वक सदस्यता समाप्त करने व निष्कासून करने की धमकी दी जा रही है जो कि अनुचित है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।